RNI .NO. MPBIL / 2013/ 54381
डाक पंजीकरण संख्या MP/IDC/1619/2024-2026

संपादकः- डॉ. देवेन्द्र मालवीय

12 वर्ष

दैनिक सद्भावना पाती

...प्राणियों में सद्भावना हो...

www.sadbhawnapaati.com Email: sadbhawnapaatinews@gmail.com इंदौर, गुरुवार ● 09 जनवरी , 2025 वर्षः-12 अंक -252 मूल्य -1 रु. कुल पृष्ठ - 8

अब एमपी सरकार युवाओं को देगी सेना-पुलिस की ट्रेनिंग

सीएम ने भोपाल में रिमोट दबाकर लॉन्च की 2 स्कीम; अब संभाग स्तर पर होंगे प्रशिक्षण

भोपाल। मध्यप्रदेश के युवाओं को अब सरकार सेना, पुलिस और पैरा मिलिट्री की ट्रेनिंग भी देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को भोपाल में पार्थ स्कीम यानी, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर की शुरुआत की। एक अन्य योजना, मध्यप्रदेश युवा प्रेरक अभियान को भी उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर लॉन्च किया। खेल मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद थे। सरकार संभाग स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षण देगी। सीएम डॉ. यादव टीटी स्टेडियम में चल रहे 28वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहां 6 जनवरी से युवा उत्सव चल रहा था। प्रदेशभर के करीब 350 युवाओं में से 45 का चयन राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए किया गया है, जो दिल्ली में अपना प्रदर्शन करेंगे। खेल मंत्री सारंग ने बताया, इस योजना में प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरा मिलिट्री आदि में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती पूर्व ट्रेनिंग दी जाएगी। खेल विभाग की संभाग स्तरीय अधोसंरचना में भी युवाओं को प्रशिक्षण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने खेल विभाग की पार्थ योजना और व एमपीवायपी (मध्यप्रदेश युवा प्रेरक

अभियान) का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत 2047 से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। योजनाओं में युवाओं के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, जो संभाग स्तरीय रहेगा। इसमें उन्हें शारीरिक दक्षता (फिजिकल टेस्ट),

लिखित परीक्षा (सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि) एवं व्यक्तित्व विकास के लिए एक्सपर्ट ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग सेंटर का संचालन संबंधित जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी करेंगे। इसके लिए ग्रामीण युवा समन्वयक और विभागीय कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जाएगा। भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की योजना स्ववित्त पोषित होगी। इसके लिए प्रशिक्षणार्थी से प्रतिमाह निर्धारित शुल्क लिया जाएगा।

युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने एमपीवायपी पोर्टल- मंत्री सारंग ने बताया, खेल विभाग ने प्रदेश के सभी युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए एमपीवायपी पोर्टल तैयार किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास, कॅरियर मार्गदर्शन और रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। यह प्लेटफॉर्म प्रदेश के सभी युवाओं के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करेगा, जहां युवा अपनी प्रतिभा को निखारकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे।

12 जनवरी को पीएम के सामने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे युवा- टीटी नगर स्टेडियम में 6 जनवरी से युवा उत्सव चल रहा था, जिसका समापन आज हो गया। इसमें 7 विधा की प्रतियोगिता हुई। जिसमें लोक गीत, समूह लोक गायन, पेंटिंग, भाषण, विज्ञान मेला, कहानी लेखन और कविता लेखन शामिल हैं। प्रदेश के 10 संभाग से 350 प्रतिभागी 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। राज्य स्तरीय युवा उत्सव के विजेता 10-12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा उत्सव में हिस्सा लेंगे। 12 जनवरी को चयनित टीम नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

बांग्लादेश दरकिनार, भारत में ही रहेंगी शेख हसीना

● सरकार ने बढ़ाया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री का वीजा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने बांगलादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना की वीजा बढ़ा दिया है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब ढाका में उनकी प्रत्यर्पण की मांग तेज हो रही है। शेख हसीना पिछले अगस्त में देश छोड़कर भारत आई थीं। बांगलादेश में उनके खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। सूत्रों के मुताबिक, उनका वीजा हाल ही में बढ़ाया गया है, ताकि वह भारत में पहले की तरह रह सकें। सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने उन्हें शरण नहीं दी है क्योंकि भारत में शरणार्थियों के लिए कोई विशेष

कानून नहीं है। बांगलादेश के अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए 23 दिसंबर को एक डिप्लोमैटिक नोट भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा था। हालांकि, भारत सरकार ने अब तक इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ढाका ने प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। इस बीच बांगलादेश की सरकार ने 97 लोगों के पासपोर्ट रद्द करने का निर्णय लिया है, जिनमें शेख हसीना का नाम भी शामिल है। इन लोगों पर जुलाई में हुए प्रदर्शनों में कथित रूप से लोगों को जबरन गायब कराने और हत्याओं में शामिल होने के आरोप हैं। बांगलादेश के इमिग्रेशन और पासपोर्ट विभाग ने यह घोषणा की है।

इसरो चेयरमैन का ऐलान वी नारायणन को कमान

● चंद्रयान-3 वाले एस सोमनाथ लेंगे इसरो से विदा

नई दिल्ली (एजेंसी)। चंद्रयान-3 के रूप में भारत को ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाले इसरो चीफ एस सोमनाथ की विदाई का समय आ गया है। उनका कार्यकाल 14 जनवरी को पूरा हो रहा है। मंगलवार को सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख का भी ऐलान कर दिया है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार, डॉक्टर वी नारायणन पद संभालने जा रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर वी नारायणन बड़ा नाम हैं। उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग

में पीएचडी हासिल की है। फिलहाल, वह लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निदेशक हैं। भारतीय अंतरिक्ष संगठन में चार दशक से ज्यादा के अनुभव के दौरान वह कई अहम पदों पर रहे हैं। खबर है कि वह रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन के विद्वान हैं। उनकी उपलब्धियों में सी 25 क्रायोजैनिक प्रोजेक्ट शामिल है। वह इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इसरो के अनुसार, डॉक्टर नारायणन की साल 1984 में इसरो में एंट्री हुई थी। शुरुआत दौर में करीब साढ़े चार सालों में उन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में साउंडिंग रॉकेट्स, ऑगमैंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के सॉलिड प्रोपल्शन क्षेत्र में काम किया। उन्होंने साल 1989 में खड़गपुर से क्रायोजैनिक इंजीनियरिंग में एम टेक किया है। वह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काउंसिल-स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अध्यक्ष भी हैं। खास बात है कि लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट और कार्यक्रमों को लेकर फैसले लेती है। साथ ही वह गगनयान के लिए यानी ह्यूमन रेटेड सर्टिफिकेशन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।

राजघाट परिसर में बनेगी प्रणब मुखर्जी की समाधि

● मोदी सरकार का बड़ा फैसला, भूमि चिन्हित करने को मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 'राष्ट्रीय स्मृति' परिसर यानी राजघाट परिसर के अंदर एक विशेष स्थल को चिन्हित करने को मंजूरी दी है। लेखिका और प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और बाबा के लिए एक स्मारक बनाने के उनके सरकार के फैसले के लिए दिल से आभार और कृतज्ञता व्यक्त की। यह और भी अधिक सराहनीय है, क्योंकि हमने

इसके लिए नहीं कहा था। प्रधानमंत्री के इस अप्रत्याशित दयाभाव और कृतज्ञता से मैं बहुत प्रभावित हूं। शर्मिष्ठा ने इसके साथ ही पीएम मोदी से अपनी मुलाकात और केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय की चिट्ठी भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने लिखा है, बाबा (प्रणब मुखर्जी) कहते थे कि राजकीय सम्मान के लिए कहा नहीं जाना चाहिए, बल्कि वह खुद ऑफर किया जाता है। मैं बहुत आभारी हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा की याद और सम्मान में ऐसा किया। हालांकि, इससे बाबा पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह अब इस दुनिया में नहीं हैं और वह प्रशंसा या आलोचना से परे रहे हैं लेकिन उनकी बेटी होने के नाते मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। प्रणब मुखर्जी जुलाई 2012 से जुलाई 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे।

कांग्रेस-बीजेपी नेताओं को फिल्म दिखाएंगे पूर्व सीएम दिग्विजय

● 13 जनवरी को जंगल सत्याग्रह का प्रीमियर शो; सीएम-वीडी को पूर्व सीएम ने दिया निमंत्रण

भोपाल। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को फिल्म दिखाएंगे। 13 जनवरी को विधानसभा के मानसरोवर सभागार में फिल्म जंगल सत्याग्रह का प्रीमियर शो आयोजित होगा। दिग्विजय सिंह ने इस शो के लिए कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों और मंत्रियों समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण भेजा है। शनिवार शाम को दिग्विजय सिंह ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इस फिल्म के प्रीमियर शो में आने का निमंत्रण दिया। दिग्विजय सिंह के पीएस सचिन वत्स और मीडिया कोऑर्डिनेटर योगेंद्र सिंह परिहार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को भी निमंत्रण भेजा। साथ ही, मोहन सरकार के मंत्रियों और बीजेपी विधायकों को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बहुचर्चित आंदोलन जंगल सत्याग्रह में बैतूल के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1930 में विद्रोह का बिगुल फूंका था।

डीएम-एसपी बताएं हाथरस में 121 मौतों का जिम्मेदार कौन?

● हाईकोर्ट बोला-आपको जिम्मेदार क्यों न माना जाए, कोर्ट में आकर बताएं

हाथरस (एजेंसी)। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान 2 जुलाई, 2024 को भगदड़ से 121 लोगों की मौत हुई थी। इससे नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस के तत्कालीन डीएम और एसपी को जवाबी

हलफनामे के साथ 15 जनवरी को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है- हादसे का जिम्मेदार कौन है। बदइंतजामी के लिए क्यों न आपकी जिम्मेदारी तय की जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने भगदड़ मामले में आरोपी महिला मंजू देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने प्रयागराज डीएम और पुलिस कमिश्नर को हाथरस की घटना से सबक लेते हुए महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए। कोर्ट ने आदेश की कॉपी डीएम हाथरस, गृह सचिव उत्तर प्रदेश, आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को भेजे हैं।

पीएम मोदी ने काम करने का बदल दिया है नजरिया

● जयशंकर बोले-पहले की सरकारें कहती थीं-चलता है ● विदेश मंत्री ने कहा-अब होगा कैसे नहीं वाला एटिट्यूड

भुवनेश्वर (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारों के काम करने का नजरिया बदल दिया है। उन्होंने देश को 'चलता है' से 'होगा कैसे नहीं' वाला एटिट्यूड दिया है। जयशंकर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में बोल रहे थे। भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 9 जनवरी को सुबह 10.00 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। पीएम गुरुवार को भारत की वैश्विक भागीदारी के बढ़ते महत्व और देश के भविष्य को आकार देने में प्रवासी समुदाय की भूमिका पर बोलेंगे। इससे

पहले जयशंकर ने बुधवार को वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने में भारत की युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की एक याद साझा की। उन्होंने कहा कि सिंधु ने पीएम को यूथ आइकन बताया था। सिंधु ने कहा था कि पीएम मोदी ने देश को चलता है से होगा कैसे नहीं वाला एटिट्यूड दिया है। 50 देशों से हजारों प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे ओडिशा के भुवनेश्वर में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हो रहा है। इसमें 50 देशों से हजारों प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सम्मेलन की मुख्य अतिथि हैं।

विश्वविद्यालय क्षेत्रीय संसाधनों की संभावनाओं को पहचानेः राज्यपाल

● वर्तमान की मांग और भावी संभावनाओं पर कार्ययोजना करें तैयारःसीएम ● राजभवन में हुई शासकीय विश्वविद्यालय के कुलगुरुओं की विशेष बैठक

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं में उच्च गुणवत्ता को लक्ष्य बनाए। लक्ष्य और प्राप्ति के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों को पर्याप्त स्वायत्ता दी गई है। जरूरी है कि कुलगुरु अपनी क्षमताओं, विश्वविद्यालय के संसाधनों और आस-पास के परिवेश के अनुसार विकास की संभावनाओं की पहचान करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में अपने सीमित दायरे से बाहर निकलें। वर्तमान की मांग और भविष्य की संभावनाओं पर कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि टॉस्क फोर्स बना कर समय-सीमा में सभी विश्वविद्यालयों की कार्ययोजना तैयार कराई जाए। राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को राजभवन में आयोजित शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कुलगुरुओं से कहा है कि विद्यार्थी कल्याण के विषयों के प्रति संवेदनशील रहें। अभिभावक अपने बच्चें सरकार के भरोसे पर शासकीय विश्वविद्यालयों में भेजते हैं। उनकी देख-भाल पालक के दृष्टिकोण के साथ की जाए। उन्होंने कहा कि कुलगुरु नियमित

आधार पर छात्रावास, मेस, खेल सुविधाओं और कक्षाओं का नियमित निरीक्षण भी करें। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाने वाले पाठ्यक्रमों पर फोकस करें। डिग्री, डिप्लोमा के साथ ही मांग आधारित पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किये जाएं। स्थानीय उद्योगों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की आवश्यकताओं के अनुसार मानव संसाधन की उपलब्धता के रोजगार लिए संबद्ध विषयों के अध्ययन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय में खेल सुविधाओं की उपलब्धता और उनके उन्नयन के लिए भी विशेष प्रयास करने की जरूरत बताई। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि रेडक्रास की गतिविधियों में विद्यार्थियों की अधिकाधिक सहभागिता की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय बहु विषयक आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय बनें। परम्परागत विषयों के साथ ही मांग आधारित और रोजगार की उच्च संभावनाओं वाले कोर्स प्रारंभ करने विशेष प्रयास करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रदान स्वायत्ता के आधार पर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाएं। विद्यार्थियों को प्रवेश की सुविधा, उत्कृष्ट शिक्षा, समय पर परीक्षा और तत्काल परिणाम घोषणा के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था को बढ़ावा दें। इसी तरह प्रवेश के समय ही अंकसूची और डिग्री वितरण के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया जाए, जिससे विद्यार्थियों के डीजी लॉकर में उनकी त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालयों को पूरा सहयोग सरकार दे रही है। विश्वविद्यालयों को वित्तीय, भौतिक और मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में सरकार ने नवीन पहल कर संसाधन सम्पन्न बनाया है।

दैनिक
सद्भावना पाती
इंदौर, गुरुवार 09 जनवरी , 2025

घर वालों का खौफ : मेले में चोरी हुए पैसे तो... रच डाली ऐसी साजिश

बुधनी। अगर आपके पैसे कहीं गुम हो जाएं तो या तो आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पुलिस में शिकायत करेंगे या फिर घर वालों को सारी सच्चाई बता देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जहां बुधनी में एक शख्स के पैसे चोरी हो गए तो उसने खुद के गुम होने की झूठी कहानी ही गढ़ दी। उसने नर्मदा नदी में डूबने का नाटक किया और पुलिस को गुमराह किया। लेकिन अंत में उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया और वह पकड़ा गया।दरअसल, भैरूंदा के निम्नगांव गांव निवासी रमेश बाकरिया मेला घूमने गया था। इस दौरान उसके पैसे चोरी हो गए। जिसके बाद वह पूरी प्लानिंग के साथ 29 दिसंबर को सोमवती अमावस्या पर घर से नहाने के लिए निकला। उसने नर्मदा घाट पर बाइक खड़ी की, कपड़े रखे और बुआ के लड़के के साथ गाड़ी से रेहटी पहुंच गया। इधर शाम तक बच्चे के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत की। जिसके बाद एक टीम उसकी तलाश में जुट गई। इस दौरान रमेश के कपड़े और बाइक नर्मदा किनारे मिली जिससे परिजनों को लगा कि उनका बेटा नहाने के दौरान नर्मदा में डूब गया। पुलिस ने भी गोताखोरों की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन शव नहीं मिला। 2 दिन बाद रहस्यमय तरीके से रमेश नहर किनारे डीमावर गांव के पास पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस उसे सिविल अस्पताल भेरूंद ले गई, जहां से उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शक के आधार पर रमेश के बुआ के लड़के को बुलाकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि हमने तो गुम होने का नाटक किया था। पुलिस हम तक पहुंच न जाए इसलिए रमेश शरीर पर मिट्टी लगाकर नहर के किनारे लेट गया और मैंने पुलिस को सूचना दे दी।

पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद में महिला की पिटाई

शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सबसे चर्चित रही रामाबाई हॉस्पिटल के जमीन विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जमीन से जुड़े विवाद के मामले को लेकर एक महिला के साथ हुई मारपीट छेड़छाड़ बलवा की शिकायत पर भाजपा नेता पुत्र समेत 6 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में अस्पताल परिसर में उत्पात मचाने वाले भाजपा पुत्र समेत दो लोगों को शहडोल कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। वहीं इस मामले में अभी 4 से अधिक लोग फरार है । देर रात महिला के साथ मारपीट का एक विडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जिले के हृदय स्थल पर स्थित रामाबाई अस्पताल के जमीन को लेकर हो रहे विवाद के बीच हॉस्पिटल परिसर में रहने वाली रंजना तिवारी ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है, कि वह देर शाम किराना सामान लेकर आ रही थी। तभी अस्पताल कैंपस में रहने वाली शिल्पा टांडी, अपने पति के.के टांडी बेटा एरोन टांडी सहित गोल्डी दुबे, गोपाल, गोलू बिहारी सहित अन्य लोग मिलकर पहले बवाल करते हुए बाल पकड़कर उसके साथ लाठी डंडे से पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों में शिल्पा ताण्डी, ऐरोन ताण्डी, केके ताण्डी , अमित उर्फ़ गोल्डी दुबे, गोलू बिहारी, गोपाल सिंह एवं तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 74,(2), 115(2), 126(2) ,296,351(2) धारा 354,147,149,323, 341,294, 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी गोल्डी दुबे सहित गोपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है । देर रात महिला के साथ मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।

आजादी के 78 साल बाद भी छुआछूत : दलित ने बांटा प्रसाद तो सरपंच ने कर दिया सामाजिक बहिष्कार

छतरपुर। आजादी के 78 साल बाद आज भी कई गांवों में छुआछूत जैसी कुप्रथाएं खत्म नहीं हो पाई हैं। जहां बाबा बागेश्वर जात-पात को खत्म कर हिंदू एकता के लिए सनातन पद यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं उनके ही जिले छतरपुर में दलितों को छुआछूत का तंज सहना पड़ रहा है।मामला सटई थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां एक दलित व्यक्ति ने हनुमान मंदिर में पुजारी के माध्यम से प्रसाद चढ़वाया और फिर गांव के पांच ग्रामीणों को बांट दिया। जब यह बात गांव के सरपंच संतोष तिवारी को पता चली, तो उन्होंने उन पांच ग्रामीणों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जिन्होंने दलित के हाथ का प्रसाद खाया था।गांववालों का आरोप है कि सरपंच के आदेश के बाद उन्हें किसी भी शादी, तेरहवीं, चौक जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जा रहा है। इस सामाजिक बहिष्कार के चलते पांचों ग्रामीण मानसिक प्रताड़ना झेलने को मजबूर हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत एसपी से की है। इस पर बिजावर एसडीओपी शशांक जैन ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी।

लोकायुक्त के जाल में फंसा एक और पटवारी : रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा

मुरैना। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम के बिछाए जाल में एक बार फिर पटवारी फंसा है। लोकायुक्त की टीम ने दो हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पटवारी को गिरफ्तार किया है।ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को सिहोनिया हल्का में पदस्थ पटवारी सुनील शर्मा को 2 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई किसान राममोहन गुर्जर की शिकायत पर की गई। जानकारी के अनुसार, पटवारी सुनील शर्मा ने जमीन नामांतरण के एवज में किसान से 8 हजार रुपए की मांग की थी।इससे पहले वह 6, हजार रुपए की रिश्वत ले चुका था। बची हुई रकम लेने के लिए किसान से बार-बार दबाव बना रहा था। परेशान होकर किसान ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत दर्ज कराई।

आवारा कुत्तों का आतंक : 12 साल की बच्ची का हाथ काट खाया

ग्वालियर। आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर शहर से ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां 12 साल की बच्ची पर बच्चों पर स्ट्रेट डॉग ने हमला कर दिया। इसके बाद गंभीर हालत में परिजन बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है।ताजा मामला जनकगंज थाना क्षेत्र के तारागंज इलाके का है। जहां, घर के बाहर खेल रही 12 साल की दिव्यांशी पर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। बच्ची की चीख पुकार सुन आसपास मौजूद लोग और परिजन बच्ची को बचाने पहुंची। जिसके बाद परिजन बच्ची को इलाज के लिए जयरोग्य अस्पताल ले कर पहुंची।जहां बच्ची का इलाज किया जा रहा है। पागल आवारा कुत्तों ने बच्ची के हाथ का मांस खा लिया। बतादें कि, मंगलवार को 2 अस्पताल में डॉग बाइट के 187 मरीज सामने आए थे। शहर में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जिससे बच्चे और बुजुर्ग को अधिक खतरा बना हुआ है।

पीसीसी चीफ का बड़ा हमला, कहा-

भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई भाजपा

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी विधायक के घर आईटी की छापेमार कार्रवाई में 14 किलो सोना, 3 करोड़ 80 लाख नगद, 10 लग्जरी कार मिली है। घर में स्थित तालाब से तीन मगरमच्छ भी बरामद हुए हैं। करीब 200 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। वहीं इसे लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पिछले एक साल साल से सकारात्मक राजनीति करते आ रही है। बीजेपी लूट, चोरी, डकैती का पर्याय बन चुकी है। आज पेपर में आया 80 करोड़ का गबन किया गया। सागर में पूर्व विधायक के घर करोड़ों रुपए और सोना मिला। पीएम नरेंद्र मोदी कहते थे भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन बीजेपी के लोग ही भ्रष्टाचार कर रहें है। भारतीय जनता पार्टी हर तरीके की भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। पटवारी ने आगे कहा कि एक क्लर्क ने 80 करोड़ का गबन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के इनकम टैक्स का छापा पड़ा। जहां से डेढ़ सौ करोड़ की संपत्ति निकली, सोना और कैश मिला है। नरेंद्र मोदी की एजेंसियां सिर्फ कांग्रेस को पीड़ित करती है। विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी होती है। वहीं मुख्यमंत्री की जनता दरबार को लेकर कहा कि जिस दिन जनता दरबार में आई तो सीएम लठ घूमने चले गए।

नेता प्रतिपक्ष बोले– बीजेपी में ऐसे धनकुबेरों की कमी नहीं

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा- न खाऊंगा न खाने दूंगा का दावा करने वाले विश्वगुरु की पार्टी में ये क्या हो रहा. सागर के पूर्व बीजेपी विधायक और पार्षद के यहां आईटी और अन्य जांच एजेंसियों को 14 किलो सोना और 3.80 करोड़ कैश मिला ! हरवंश सिंह, राजेश केशरवानी और एक व्यापारी के यहां से 150 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई ! तीन दिन की छापेमारी के दौरान कई लग्जरी गाड़ियां भी मिली। बीजेपी में ऐसे धनकुबेरों की कमी नहीं है। जो धनकुबेर होता नहीं है, तो पार्टी में आकर हो जाता है। बीजेपी ने राजनीति को कमाई का कारोबार बना लिया और जनता को जमकर लूट रहे हैं ! भाजपा सरकार में प्रदेश कर्ज़ में डूबता जा रहा है, जबकि इनके नेता दिन-ब-दिन अमीर होते जा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया को इसका जवाब देना चाहिए। राजधानी भोपाल के मेंडोर में कार से 54 किलो सोने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि बंडा के पूर्व बीजेपी विधायक हरवंश सिंह राठौर के घर से 14 किलो गोल्ड मिला है। आईटी ने भाजपा के पूर्व विधायक, सागर के पूर्व पार्षद राजेश केशरवानी और इनके सहयोगियों के तीन ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें 200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। ढ्ढ की राठौर के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई मंगलवार को पूरी हो गई है। वहीं केशरवानी के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। यहां से करोड़ों के नगद, लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग के दस्तावेज मिले हैं।

ये मेरा ग्राहक है, नहीं ये मेरा है : एक कस्टमर को लेकर दो दुकानदारों के बीच मारपीट

ग्वालियर। ये मेरा ग्राहक है..नहीं ये तो मेरा ग्राहक है। इन शब्दों ने शहर के फूल बाग चौराहे पर जमकर बवाल करा डाला। आधा दर्जन से अधिक लोग आपस में एक दूसरे की लात घूंसों से मारपीट करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस को मौके पर पहुंच बवाल को शांत करना पड़ा। दरसअल शहर के फूल बाग चौराहे पर लजीज अमृतसरी नान का स्वाद ग्राहकों को दूर दराज के इलाकों से भी खींचकर यहां ले आता है। ग्राहक बड़े ही स्वाद से अमृतसरी नान का लुफ्त उठाते हैं। लेकिन यहां पर एक ग्राहक को लेकर दो अलग-अलग अमृतसरी नान स्टॉल लगाने वाले संचालकों के कर्मचारियों के बीच जमकर लात घूंसे चले। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब एक ग्राहक अमृतसरी नान खाने फूलबाग चौराहे पर पहुंचा, जैसे ही वह अमृतसरी नान स्टॉल की तरह आगे बढ़ा। वैसेही दोनों स्टॉल के कर्मचारी उसे आवाज देकर बुलाने लगें। आजादी के 78 साल बाद भी छुआछूत~ दलित ने बांटा प्रसाद तो सरपंच ने कर दिया सामाजिक बहिष्कार, स्क्क से शिकायत करने पहुंचे ग्रामीण इस बीच ग्राहक सफेद रंग के स्टॉल पर जाकर बैठ गया और नान का ऑर्डर दे दिया। जिसके बाद पूरा विवाद तूल पकड़ गया। दोनों ही एक दूसरे से कहने लगे की ÷ये मेरा ग्राहक है नहीं ये तो मेरा ग्राहक है। शुरुआती गहमागहमी के बीच ग्राहक स्वाद लेकर अमृतसरी नान खाता रहा। दूसरी तरफ दोनों स्टॉल संचालक के कर्मचारी आपस में एक दूसरे के साथ मुंहवाद करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। जमकर लात घूंसों से एक दूसरे की मारपीट करने लगे। आसपास खड़े लोगों ने विवाद बढ़ने पर पड़ाव थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत कराया। वहीं दूसरी तरफ मौका पाकर ग्राहक रफूचक्कर हो गया। जब इस बात की जानकारी दोनों अमृतसरी नान स्टॉल संचालकों के कर्मचारियों को लगी, तो वह भी कहने को मजबूर हो गए कि यह ग्राहक भगवान था या शैतान।

राजा भैया के बाद दूसरे ऐसे नेता जिन्होंने पाला मगरमच्छ

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी विधायक हरवंश सिंह राठौर के घर आईटी की छापेमार कार्रवाई में कई बड़े खुलासे हुए हैं। करीब 200 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। वहीं उनके घर में स्थित तालाब से तीन मगरमच्छ भी बरामद हुए हैं। कहा जा रहा है कि हरवंश राठौर, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बाद दूसरे ऐसे नेता है, जिन्होंने मगरमच्छ पाला है।शनिवार 5 जनवरी को मध्यप्रदेश के सागर में आयकर विभाग ने पूर्व विधायक और बीड़ी उद्योगपति के घर दबिश दी थी। बीजेपी के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर, भाजपा के पूर्व पार्षद और बीड़ी व्यवसायी राजेश केशरवानी के घर पर छापा मारा था। इस दौरान पूर्व स्न्न के घर से 14 किलो सोना (त्रश्चद्यस्र) मिला है। साथ ही 3 करोड़ 80 लाख नगद और 10 लग्जरी कार भी बरामद की गई। यह गाड़ियां कर्मचारी और अन्य लोगों के नाम पर है। बताया जा रहा है कि हरवंश राठौर और राजेश केशरवानी, कंस्ट्रक्शन, बीड़ी समेत जमीनों के कारोबार से जुड़े हैं।

तीन मगरमच्छ भी मिले

हरवंश राठौर के घर के अंदर एक छोटे तालाब में मगरमच्छ भी मिला है। आयकर विभाग ने तीन मगरमच्छ बरामद किया है। जबकि मगरमच्छ पालना गैरकानूनी है। वहीं आईटी ने इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी है। इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी के प्रतापगढ़ की कुंडा रियासत से संबंध रखने वाले राजा भैया के बाद हरवंश राठौर दूसरे ऐसे नेता है जिन्होंने मगरमच्छ पाला है। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और मायावती मुख्यमंत्री थी। तब बसपा सुप्रीमो और राजा भैया की अदावत खुलेआम चल रही थी। इस बीच मायावती ने राजा भैया पर एक्शन लिया और उन्हें जेल भी भेज दिया था। इस दौरान उनके बेंती महल की भी तलाशी ली गई। जहां एक बड़ा तालाब भी था। कहा जाता है कि राजा भैया इस तालाबा में मगरमच्छ पालते हैं। राजा भैया के पास कई मगरमच्छ हैं और राजा भैया अपने दुश्मनों को उस तालाब में फिकवा देंते हैं।राजा भैया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे किसी भी तालाब में मगरमच्छ नहीं पाले जाते हैं, जिस तालाब की बात दशकों से होती है, वो तालाब 600 बीघा में फैला हुआ है। उस तालाब में मछली पालन का काम होता है। राजा भैया ने कहा था कि जिस तालाब में मछली पालेगा वहां कोई मगरमच्छ नहीं पालेगा, क्योंकि मगरमच्छ मछलियों को खा जाएगा। इस दौरान राजा भैया ने ये भी कहा था जहां हमारा तालाब है, वहां करीब ही गंगा जी भी हैं, हो सकता है कि कभी कोई मगरमच्छ गंगा जी के माध्यम से हमारे तालाब में आ पहुंचा हो, यह अलग बात है, लेकिन हम मगरमच्छ नहीं पालते हैं।

पूर्व बीजेपी विधायक के घर से मिला 14 किलो गोल्ड: 3.80 करोड़ नकद, 10 लग्जरी कारें भी बरामद

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के बाद अब पूर्व विधायक के घर से 14 किलो सोना मिला है। आयकर विभाग की कार्रवाई में 3 करोड़ 80 लाख नगद भी बरामद हुए। इस दौरान 10 लग्जरी कार भी मिली। करीब 200 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। दो दिन पहले आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की थी। 5 जनवरी को मध्य प्रदेश के सागर में कल सुबह आयकर विभाग (आईटी) सहित अन्य जांच एजेंसियों ने पूर्व विधायक और बीड़ी उद्योगपति के घर दबिश दी थी। आईटी की टीम की रेड से मोहल्ले सहित पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। आयकर विभाग ने आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी को लेकर जांच पड़ताल की। जिसमें कई अहम खुलासे हुए।बीजेपी के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर, भाजपा के पूर्व पार्षद और बीड़ी व्यवसायी राजेश केशरवानी सहित एक अन्य के घर पर छापा मारा था। कई गाड़ियों में सवार होकर जांच एजेंसियों की टीमें अलसुबह पहुंची है। जांच के दौरान पूर्व स्न्न के घर 14 किलो सोना मिला।आईटी की कार्रवाई में तीन करोड़ 80 लाख नगद और 10 लग्जरी कार भी मिली। यह गाड़ियां कर्मचारी और अन्य लोगों के नाम पर है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक हरवंश राठौर, पूर्व पार्षद राजेश केशरवानी की करीब 200 करोड़ की संपत्ति है। हरवंश राठौर और राजेश केशरवानी, कंस्ट्रक्शन, बीड़ी समेत जमीनों के कारोबार से जुड़े हैं। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है।

पीएसी बैठक में नाराजगी पर कमलनाथ की सफाई

एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा– हम सब कांग्रेसी एक हैं, विवाद का कोई सवाल ही नहीं

भोपाल (नप्र)। सोमवार शाम एमपी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (पीएसी) की ऑनलाइन बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की नाराजगी की खबरें सामने आईं। बैठक में कांग्रेस में होने वाली नियुक्तियों, सूचनाओं और एजेंडे को लेकर कमलनाथ की नाराजगी की बातें मीडिया में आई। इन खबरों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद सफाई दी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर लिखा- कांग्रेस की मजबूती के लिए और प्रदेश की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हम सब कांग्रेसजन एक हैं। विवाद का कोई प्रश्न नहीं है। पिछले दिनों हुई प्रदेश की राजनैतिक मामलों की समिति की बैठक को लेकर मीडिया में नाराज़गी के जो कयास लगाए जा रहे हैं, वे निराधार हैं।

पटवारी ने लिखा- बीजेपी की सिर फुटव्वल से ध्यान भटकाने की कोशिश- कमलनाथ के ट्वीट का रिट्वीट करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लिखा- प्रदेशवासियों, मध्य प्रदेश जनसंपर्क अब केवल डॉ. मोहन यादव की सत्ता के कारनामों को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। एमपी बीजेपी में मची लूट, सरकारी भ्रष्टाचार और सिर-फुटव्वल से ध्यान भटकाने के लिए यही लोग मीडिया में झूठी खबरें फैलाते हैं। मुख्यमंत्री के मातहत विभाग का पर्दाफाश करने के लिए कमलनाथ जी का बहुत-बहुत आभार।

108 की टक्कर से घायल युवक की मौत

सिग्नल पर खड़े वाहन ने मारी थी टक्कर; 3 दिन पहले ही मां हुई है डिस्चार्ज

भोपाल (नप्र)। भोपाल के लालघाटी स्थित सिग्नल पर 1 जनवरी को बाइक सवार मां-बेटे सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार कर रहे थे। तभी पीछे से 108 एम्बुलेंस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बेटे की बुधवार की सुबह 11 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई। उसकी मां की तीन दिन पहले इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी हो चुकी है। कोहेफिजा पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के जीजा नासिर अली के मुताबिक साला सोहेल अली पुत्र शब्बीर अली 27 वर्ष निवासी तूमड़ा खजूरी एक जनवरी को मां रानी बी को बाइक से भोपाल ला रहा था। यहां अस्पताल में भर्ती एक रिश्तेदार को देखने के लिए दोनों आ रहे थे। लालघाटी सिग्नल पर खड़ी गाड़ी में 108 ने टक्कर मारी थी। इलाज के दौरान बुधवार की सुबह सोहेल की मौत हो गई। मां को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

तीन साल पहले हुई थी शादी– सोहेल ड्राइवर था। तीन साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। हादसे के दिन मां-बेटे बीमार रिश्तेदार को देखने भोपाल आ रहे थे। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

नर्सिंग कॉलेज की कॉउंसलिंग प्रक्रिया समय-सीमा में करें पूर्ण : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नर्सिंग कॉलेजों की कॉउंसलिंग प्रक्रिया एवं मान्यता से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित समय-सीमा के भीतर समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

एचएमपीवी वायरस की स्थिति पर रखें सतत निगरानी

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मेडिकल कॉलेजों में पे-प्रोटेक्शन से संबंधित प्रस्ताव को तैयार कर कैबिनेट अनुमोदन के लिए शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने एचएमपीवी वायरस की वर्तमान स्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप सतत निगरानी रखने और आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तैयारी रखने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार हेतु अधोसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त स्वास्थ्य श्री तरुण राठी और संचालक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (नर्सिंग एवं पैरामेडिकल) श्री मनोज सरियाम उपस्थित रहे।

प्रशासनिक निर्णयों में न हो देरी, सभी औपचारिकताएं समय से करें पूर्ण : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रशासनिक निर्णयों में किसी प्रकार की देरी न हो और सभी औपचारिकताएं समय पर पूर्ण की जाएं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आईपीएचएस मानकों के अनुरूप नवीन स्वीकृत पदों, नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं और उन्नत स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्तियों की पूर्ति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नर्सिंग भर्ती और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त किया जा सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया और पैरामेडिकल कॉउंसिल की गतिविधियों की समीक्षा की।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सीधी भर्ती के साथ पदोन्नति के पदों की रिक्तियों पर भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानव संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित कर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने पैरामेडिकल संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की और नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के पैरामेडिकल विद्यार्थियों की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और उनके परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त स्वास्थ्य श्री तरुण राठी, संचालक स्वास्थ्य श्री दिनेश श्रीवास्तव, संचालक स्थापना श्रीमती मल्लिका नागर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

भुसावल-कटनी एक्सप्रेस चोपन तक चलेगी, सिंगरौली से बढ़ेगा रेल संपर्क

यह ट्रेन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी

जबलपुर(नप्र)। जबलपुर से सिंगरौली और चोपन तक की यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने भुसावल-कटनी एक्सप्रेस को चोपन तक चलाने की तैयारी लगभग पूर्ण कर ली है। भुसावल-कटनी-चोपन ट्रेन की प्रस्तावित समय-सारिणी और ठहराव को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए रेल बोर्ड के पास भेजा गया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी से ट्रेन का संचालन आरंभ हो जाएगा। अभी जबलपुर से सिंगरौली के लिए दो सीधी ट्रेन चलती हैं।

स्पेशल ट्रेन के रूप में लिया ट्रायल– भुसावल-कटनी एक्सप्रेस को चोपन तक चलाने का ट्रायल किया जा चुका है। रेलवे ने गत वर्ष दीपावली और छठ पूजा के समय पर ट्रेन को कटनी से चोपन के मध्य स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया था। उस समय ट्रेन को भुसवाल-कटनी और कटनी-चौपन के मध्य दो अलग-अलग ट्रेन के रूप में संचालित किया गया। कटनी-चौपन रेलखंड में स्पेशल ट्रेन बनकर चलने के कारण यात्री किराया अपेक्षाकृत अधिक था। यात्री नहीं मिलने पर ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया था।

अभी कटनी में 16 घंटे खड़ा रहता है रैक– भुसावल से कटनी पहुंचने के बाद इस ट्रेन का रैक लगभग 16 घंटे कटनी में खड़ा रहता है। इतने समय में ट्रेन कटनी-चोपन-कटनी का फेरा पूरा कर सकती है। इसलिए ट्रेन को अब उसी रैक से भुसावल से चोपन तक सीधे एक्सप्रेस के रूप में चलाने की योजना बनाई गई है।

विस्तारित ट्रेन का ठहराव कटनी जंक्शन के स्थान पर कटनी साउथ होगा। ट्रेन के ठहराव का पुनर्निर्धारण करते हुए गति में वृद्धि का प्रस्ताव बनाया है। स्पेशल के स्थान पर नियमित ट्रेन दौड़ाने का विचार है, ताकि यात्री सामान्य किराए पर यात्रा कर सकें।

दैनिक
सद्भावना पाती

...प्राणियों में सद्भावना हो...

इंदौर पाती

3

इंदौर, गुरुवार 09 जनवरी , 2025

वैध और अवैध कॉलोनियों में भी नंबर वन है अपना इंदौर

प्रदेश की 30% वैध कॉलोनियां सिर्फ इंदौर में... वहीं सैकड़ों अवैध कालोनियों का मकड़जाल भी यहाँ

डॉ. देवेंद्र मालवीय
9827622204
दैनिक सद्भावना पाती

इंदौर। 40 लाख से अधिक की आबादी वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर जो स्वच्छता में अव्वल और न केवल अपने विकास के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अब यह वैध और अवैध कॉलोनियों के मामले में भी चर्चा में है। जहां एक ओर इंदौर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के मामले में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर अवैध कॉलोनियों का जाल भी तेजी से फैल रहा है, जो न केवल शहर के सौंदर्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) प्राधिकरण की वेबसाइट के अनुसार, मध्य प्रदेश में लगभग 6800 पंजीकृत प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से करीब 2000 प्रोजेक्ट्स इंदौर जिले में रजिस्टर्ड हैं। मतलब प्रदेश के कुल पंजीकृत प्रोजेक्ट का लगभग 30त्न वैध कॉलोनियों सिर्फ इंदौर में है, इस आंकड़े के अनुसार इंदौर प्रदेश में सबसे अधिक वैध कॉलोनियों वाला शहर है। ये कॉलोनियां आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से लैस हैं और शहर की विकास यात्रा का अहम हिस्सा बनी हुई हैं। इंदौर में रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। शहर के वर्ल्ड क्लास एंबिएंट के साथ विकसित होने वाली कॉलोनियों में हाई-एंड सुविधाएं जैसे सीवेज सिस्टम, सड़कों पर लाइटिंग, पानी की आपूर्ति और ग्रीन बेल्ट जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं ने इंदौर को एक मजबूत रियल एस्टेट हब बना दिया है।

प्रशासन की कार्रवाई

हाल ही में, इंदौर के जिला कलेक्टर ने इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन ने पटवारियों के माध्यम से इन कॉलोनियों की जांच शुरू की है।

तहसीलदार और एसडीएम द्वारा 100 से अधिक प्रकरणों की पहचान की गई है। इनमें से 10 से अधिक मामलों में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई जा चुकी है, और लगभग 90 प्रकरणों पर सुनवाई जारी है। ऐसे प्रकरणों में एफआईआर दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है।

अवैध कॉलोनियां के गढ़ माने जाने वाले मुख्य क्षेत्र

इंदौर जिले के कई प्रमुख गांवों और क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का जाल फैला हुआ है। इनमें प्रमुख रूप से आशापुरा, उमरियाखुर्द, उमरीखेडा, क़स्बा इंदौर, काली बिल्लौद , कालीबिल्लोद, केलोद करताल, कोदरिया, कोर्डियाबर्डी, खरडाखेडा, गवली पलासिया, गोकन्या, छोटा बांगडदा, जामखुर्द, जामन्या, जामन्या खुर्द, टिगरयाबादशाह, डोंगरगाँव, दतोदा, नावदापंथ, निपान्या, नेऊगुराडिया, नेनोद, पिपल्या लोहार, पिपल्याराव, पीरकराडिया, बडगोंदा, बरदरी, बांक, बावल्याखुर्द , बिलावली, बिहाडिया, बुढानिया, बुढी बरलई, भाग्या, मांगल्या सड़क, मेठवाड़ा, मोरोद नेहरु, मोरोद नेहरु, राऊ, रावेर, सनावदिया, सावेर, सिमरोल, सुकल्या, हुकमाखेड़ी जैसे गांव शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों के निर्माण से संबंधित सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। इन कॉलोनियों का मकड़जाल इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है कि प्रशासन को इन्हें हटाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। फर्जी कॉलोनाइजर ने अवैध कॉलोनियों में सरकारी भूमि, ग्रीन बेल्ट और कांकड़ (गांव का रास्ता) जैसे क्षेत्रों पर भी कब्जा किया गया है। वन भूमि और केचमेंट एरिया पर भी अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जो न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि नियमों और कानूनों का भी उल्लंघन है। इन अवैध कॉलोनियों के लिए जिम्मेदार कॉलोनाइजर आमतौर पर रेरा और नगर निगम के नियामक प्राधिकरण से बचते हुए इन कॉलोनियों का निर्माण करते हैं। इस दौरान नगर निगम और रेरा द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे ऐसे कॉलोनाइजरों का मनोबल बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप प्रशासन को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है।

अवैध कॉलोनियों के मकड़जाल से जूझता शहर

इंदौर में वैध कॉलोनियों के अलावा अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल भी तेजी से फैल रहा है। पुरानी बसाहट वाली अवैध कालोनियों की संख्या सैकड़ों मे पहले से थी, वर्तमान में भी यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अवैध कॉलोनियों के कारण शहर में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने हाल ही में इन अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने के प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन बावजूद इसके इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रशासन की लापरवाही और अवैध कॉलोनाइजरों की मिलीभगत के कारण यह स्थिति और भी जटिल हो गई है। अवैध कॉलोनियों के निवासी जहां सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं इन कॉलोनियों में स्थाई रूप से रहने वाले लोग भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या सीवेज और जल आपूर्ति की है, जहां न तो पर्याप्त जल आपूर्ति हो रही है और न ही ड्रेनेज सिस्टम का उचित प्रबंधन किया जा रहा है। कई कॉलोनियों में बिजली की स्थिति भी बेहद खराब है, और यातायात के लिए बुनियादी सड़कें तक नहीं हैं।

करोड़ों की बैंकिंग फ्रॉड करने वाले आईसीआईसीआई बैंक कर्मचारियों के गिरोह का पर्दाफाश

- बैंकिंग सिस्टम की सुविधा का दुरुपयोग कर इंदौर सहित पंजाब, गुजरात, तेलंगाना के करीब 01 दर्जन व्यापारियों के साथ करोडों रूपये की धोखाधडी करने वाले आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी पुलिस की गिरफ्त में
- आरोपी कर्मचारी ने खुद पासवर्ड बदलकर की एक दर्जन खातों से आनलाईन शॉपिंग, लाखों रूपये कीमत के एप्पल-16 प्रोमेक्स, सैमसंग एस-24 अल्ट्रा जैसे मोबाइल फोन एंव गोल्ड खरीदा

इंदौर। वर्तमान समय मे लगातार चुनौती बनते जा रहे सायबर/ओटीपी फ्रॉड से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने हेतु पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह एवं अति. पुलिस आयुक्त अमित सिंह द्वारा निर्देश दिए गए है। इसी तारतम्य में आईसीआईसीआई बैंक इंदौर द्वारा थाना विजयनगर पर बैंक के दर्जन भर करंट अकाउंट खातों से बिना ओटीपी/पासवर्ड बताये आनलाईन बैंकिंग के माध्यम से करोडो रूपये की धोखाधडी करने की शिकायत की गई थी, जिस पर थाना विजयनगर पर अप. क्र. 851/24 धोखाधडी की धाराओं में पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। पुलिस उपायुक्त जोन 2 अभिनय विश्वकर्मा एवं अति. पुलिस उपायुक्त ज़ोन 2 अमरेंद्र सिंह, एसीपी विजयनगर आदित्य पटले (आईपीएस) द्वारा थाना प्रभारी विजयनगर चंद्रकांत पटेल को शीघ्र प्रकरण में पतारसी कर, आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए निर्देशित किया। उक्त निर्देशों पर थाना प्रभारी विजयनगर के नेतृत्व में टीम का गठन कर त्वरित अनुसंधान कर घटना में संलिप्त आईसीआईसीआई बैंक कर्मचारी कमल कुमावत, अभिषेक मालवीय, स्टेनली जैकब व उनके साथी लवदीप सिंह को दिनांक 08/01/2024 की रात्रि में गिरफ्तार कर आरोपियों से करीब 20 लाख रूपये कीमत के मंहगे एप्पल 16 प्रोमैक्स, सैमसंग एस 24 अल्ट्रा, जेड फ्लिप 6, स्मार्ट वाचेज, गैमिग प्लेस्टेशन आदि जब्त किये गये है। सभी खाता धारकों की करीब 52 लाख रूपये की धनराशी भी वापस कराई गई है। आईसीआईसीआई बैंक विनवे वल्ड ऑफिस विजयनगर द्वारा थाना विजयनगर पर रिपोर्ट लेख कराई कि उनके बैंक के कई करंट अकाउंट्स से लगातार बिना ओटीपी एवं पासवर्ड शेयर किये धनराशी निकासी शेष पेज 4 पर...

अपर आयुक्त का आकस्मिक निरीक्षण..ठंडे मौसम में कर्मचारियों के पसीने छूटे

इंदौर। इंदौर नगर निगम मुख्यालय के कार्य प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। एक दिन पहले आयुक्त शिवम वर्मा ने जनसुनवाई के दौरान जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग का आकस्मिक निरीक्षण किया। अब अपर आयुक्त मनोज पाठक ने जल यंत्रालय और गरीबी उपशमन विभाग का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान हाजिरी रजिस्टर की जांच की गई और अनुपस्थित कर्मचारियों को चिन्हित किया गया। मनोज पाठक ने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए हैं, उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।

लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के पास समपार फाटक संख्या 55 से आवागमन बंद

इंदौर। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल पर संरक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखकर समपार फाटकों के स?थान पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के पास समपार फाटक संख?या 55 के स?थान पर रोड ओवर ब्रिज निर्माण कार्य 9 जनवरी 2025 से आरंभ किया जाना है । रोड ओवर ब्रिज निर्माण किये जाने के कारण 09 जनवरी, 2025 से समपार फाटक संख?या 55 से सड़क यातायात बंद किया जा रहा है। असुविधा से बचने के लिए सड़क उपयोगकर्ता इस दौरान एमआर-4 रेलवे अंडरपास मारिमाता चौराहा का उपयोग कर सकते हैं।

महापौर द्वारा निगम के डॉक्युमेंट डिजिटलाइजेशन का शुभारंभ

- 90 लाख से अधिक दस्तावेजों को स्केन कर करेंगे सुरक्षित
- निगम के दस्तावेज ही निगम की संपत्ति है : महापौर पुष्यमित्र भार्गव

इंदौर। सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रभारी राजेश उदावत ने बताया कि नगर निगम इंदौर के डॉक्यूमेंट के डिजिटाइलेशन कार्य का महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा निगम के पुराने परिषद भवन में शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर आयुक्त शिवम वर्मा, पूर्व महापौर कृष्णमुरारी मोघे, डॉ. उमाशशि शर्मा, सभापति मुन्नालाल यादव, पूर्व सभापति अजयसिंह नरूका, महापौर परिषद सदस्य राजेश उदावत, निरंजनसिंह चौहान, मनीष शर्मा मामा, सूचना व प्रौद्योगिकी समिति सदस्य सुरेश कुरवाडे, श्रीमती शिखा संदीप दुबे, गजानंद गांवडे सहित पूर्व महापौर परिषद सदस्य, पूर्व पार्षद व अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सूचना प्रौद्योगिक समिति सदस्य व पार्षद श्रीमती शिखा संदीप दुबे ने आभार व्यक्त किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत के स्वप्न को इंदौर ने पुरा करने का आज प्रयास किया है, भविष्य में आने वाले 10 से 15 वर्ष के बाद नवीन तकनीक कैसी होगी, इसके दृष्टिगत रखते हुए, नगर निगम इंदौर द्वारा नागरिको की रोजमर्रा की चुनौती के समाधान के साथ ही निगम स्तर की आधारभूत सेवाऐं कि जानकारी व समस्या का समाधान किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से किया जावेगा, इसके लिये हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प था, ग्रीन इंदौर, क्लीन इंदौर के साथ ही डिजिटल इंदौर इसे हमने आज पूरा किया है, साथ ही नगर निगम के 90 लाख से अधिक दस्तावेजों की सुरक्षा को देखते हुए, उसको स्कैन कर सुरक्षित करने का कार्य किया है।

महापौर भार्गव ने कहा कि नगम निगम इंदौर की मुख्य संपत्ति उसके दस्तावेज है, दस्तावेज को सुरक्षित कर हमने अपनी संपति को आने वाले कई सालो के लिये सुरक्षित किया है, साथ ही मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री के सहयोग से नगर निगम स्वंय का पोर्टल निर्माण कर रहा है, जो कि आगामी 1 अप्रैल से अपना कार्य प्रारम्भ करेगा। निगम के पोर्टल के साथ ही मोबाईल एप भी तैयार कर रहा है जिसके तहत नागरिक मोबाईल के माध्यम से ही निगम की विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्राप्त करेगा। वर्तमान में नगर निगम इंदौर द्वारा डिजिटलाजेशन के कई क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसके तहत चैम्बर की जियो टैगिंग, स्ट्रीट लाईट का संचालन करना, शहर में स्थित सीटीपीटी की जानकारी आदि समस्त कार्य ऐप के माध्यम से किये जा रहे हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रभारी राजेश उदावत ने कहा कि निगम परिषद के गठन के समय हमारी परिषद ने नगर निगम इंदौर को डिजिटल नगर निगम बनाने का जो संकल्प लिया था, उसे आज महापौर भार्गव के नेतृत्व में पुरा किया है, साथ ही वर्तमान में ई नगर पालिक सिस्टम जो कि भोपाल से संचालित होता है, उसमें समय समय पर समस्या आती रहती है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए, नगर निगम स्वंय का पोर्टल निर्माण भी कर रहा है, जिसमें डिजिटल इंदौर के अंतर्गत इंदौर नगर निगम द्वारा वेब पोर्टल का निर्माण करते हुए, निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली 24 से अधिक आधारभूत सुविधाऐं प्राप्त होगी।

साथ ही निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालयो के नेटवर्क एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालयो में प्रस्तावित परियोजना का क्रियान्वयन किया जावेगा। प्रभारी उदावत ने कहा कि आज नगर निगम इंदौर के डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत एक वर्ष की अवधि के भीतर नगर निगम इंदौर के वेब बेस्ड डीएमएस एप्लीकेशन के माध्यम से 90 लाख से अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेजों व रिकार्ड्स का डिजिटलीकरण किया जावेगा। डिजिटलीकरण प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग से दस्तावेज प्राप्त कर, दस्तावेज को स्केन किया जावेगा, फिर दस्तावेज स्केन के दौरान कोई त्रुटि मिलती है तो उसका सुधार होगा, फिर डेटा एन्ट्री कर स्केन पेज की क्यूसी तैयार करना, निगम स्टाफ से क्यूसी व अनुमोदन कर सर्चेबल पीडीएफ का निर्माण किया जावेगा और उन डीएमएस पर अपलोड किया जावेगा।

मेरे साथ संबंध बनाती रही : छात्र ने की आत्महत्या, महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी से था अफेयर

इंदौर। एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक ने महिला आरक्षक के साथ संबंध और मानसिक तनाव का जिक्र किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में छात्र प्रदीप रावत (23) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने 5 पेज के सुसाइड नोट में ट्रैफिक पुलिस की एक महिला आरक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदीप रावत, जो बाग टांडा का रहने वाला था, इंदौर में किराए के मकान में रहकर बीएड की पढ़ाई कर रहा था। प्रदीप ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें महिला आरक्षक के साथ उसके संबंध और मानसिक तनाव का जिक्र किया है। प्रदीप ने लिखा है कि वह 2017 से महिला आरक्षक को जानता था। महिला आरक्षक और अन्य व्यक्ति अनुराग प्रजापत के कारण वह परेशान था। सुसाइड नोट में मोबाइल में फोटो और वीडियो का जिक्र किया गया है। साथ ही शादी को लेकर तनाव होने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। महिला आरक्षक से भी पूछताछ की जा रही है।

दैनिक सद्भावना पाती
इंदौर, गुरुवार 09 जनवरी, 2025

निगम सीमा क्षेत्र के 22 झोनों में 25 स्वीपिंग मशीनों द्वारा नियमित रूप से सफाई कार्य किया गया

● स्पॉट फाइन के द्वारा दो करोड़ 44 लाख 5 हजार 380 रुपये वसूल किए गए, सार्वजनिक व दार्शनिक स्थलों पर सफाई की व्यवस्था की गई

इंदौर। नगर पालिका निगम इंदौर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत वर्ष की उपलब्धियों का विवरण देते हुए बताया गया है कि निगम सीमा क्षेत्र के 22 झोनों में 25 स्वीपिंग मशीनों की सहायता से सफाई कार्य प्रतिदिन नियमित रूप से किया गया, जो आज भी जारी है। मुख्य मार्गों पर स्थित भवनों, दीवारों, पैदल मार्गों पर सफाई-धुलाई का कार्य भी नियमित रूप से किया जाकर आज भी किया जा रहा है। शहर के पर्यटन स्थल व सार्वजनिक स्थलों, गार्डनों, दार्शनिक स्थलों पर भी साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। इसमें फुटपाथों की सफाई व्यवस्था भी शामिल है। इसी प्रकार महापौर टास्क फोर्स का गठन किया जाकर 42 कर्मचारियों द्वारा दल बनाकर शहर के विभिन्न वार्डों में विशेष साफ-सफाई की व्यवस्था के साथ-साथ उनके सौंदर्यीकरण का कार्य सतत किया गया, वह आज भी जारी है। सार्वजनिक मार्गों पर आयोजित कार्यक्रमों, बारात, जुलूस के दौरान होने वाली गंदगी को नियंत्रित करने के साथ-साथ जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। सफाई मित्रों की कमी को भी दूर किया जाकर सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न किया गया था। मच्छरों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु फागिंग मशीन से धुआं व सीकर पंप के माध्यम से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाया जाकर डेंगू एवं लार्वा की रोकथाम की गई तथा यह कार्य आज भी निरन्तर जारी है। औषधीय का छिड़काव भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के वाणिज्यिक संस्थानों, होटल, अस्पताल, मैरिज गार्डन व अन्य संस्थानों से वर्ष 2024-2025 में 52 लाख 47 हजार 995 की वसूली की गई, जिसे निगम कोष में जमा करवाया गया है। प्लास्टिक के उपयोग पर भी सतत निगरानी की गई थी, जो आज भी की जा रही है। अमानक स्तर के प्लास्टिक के उपयोग पर 13 हजार 895 चालान बनाये गए, जिसमें 55 लाख 51 हजार 800 रुपये का अर्थदंड वसूला गया है। जन जागरूकता हेतु 卐मैं भी झोलाधारी हूं卐 कपड़े का उपयोग करने हेतु अभियान चलाया गया। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पॉट फाइन भी किए गए हैं। गंदगी करने पर स्पॉट फाइन की संख्या 15 हजार 200 है, जिसमें एक करोड़ 18 लाख 32 हजार 250 रुपये की वसूल किये गए। थूकने पर 6 हजार 507 चालान बनाए जाकर 7 लाख 81 हजार 590 रुपये वसूल किये गए। परिवहन के 2 हजार 457 चालान बनाये जाकर 20 लाख 12 हजार 900 रुपये की वसूली की गई। ओपन यूरिन के 1840 चालान बनाकर 1 लाख 80 हजार 440 रुपये वसूल किए गए। कचरा जलाने पर 46 चालान के माध्यम से 22 हजार 950 रुपये वसूल किये गए। अन्य मामलों में भी 3 हजार 600 चालानी कार्यवाही के माध्यम से 40 लाख 23 हजार 450 रुपये की वसूली की गई। इस प्रकार कुल 43 हजार 545 चालान बनाए गए थे, जिनमें कुल 2 करोड़ 44 लाख 5 हजार 380 रुपए वसूल किए गए। इसी तरह शहर को पशु मुक्त किए जाने के क्रम में सूअर उन्मूलन दल का एवं मृत पशुओं को यथा समय उठाने का कार्य सतत जारी है। गंदगी फैलाने पर भी प्रभावी नियंत्रण रखा जा रहा है।

पेज 3 का शेष

करोड़ों की बैंकिंग फ्रॉड ...

की गई है। रिपोर्ट पर अपराध धारा 318, 319, 316(4), 314, 61 बीएनएस. का पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। सभी खाताधारकों ने बताया कि उनके करंट अकाउंट से लाखों रुपये के ट्रांजेक्शन अमेजन, फ्लिपकार्ट, एप्पल, वन प्लस आदि पर किये गये हैं जबकि खाता धारकों द्वारा किसी भी व्यक्ति को ओटीपी या पासवर्ड नही बताये गये हैं। अकाउंट स्टेटमेंट के ट्रांजेक्शन की जानकारी प्राप्त करने पर सभी खाताधारकों के खातों से अमेजन, फ्लिपकार्ट, एप्पल, वन प्लस जैसी साईटो पर लाखों रूपये के ट्रांजेक्शन गिफ्ट कार्ड्स खरीदने के लिये किये जाना एवं उक्त गिफ्ट कार्ड्स विक्रय कर आरोपी- कमल कुमावत, अभिषेक मालवीय, स्टेनली जैकब द्वारा महंगे आईफोन 16 प्रोमैक्स, सैमसंग अल्ट्रा एस 24, सैमसंग जेड फ्लिप 6, आईफोन वॉच, सैमसंग स्मार्ट वॉच क्रय करना तथा तीनो आरोपियों द्वारा तनिश्क एप से ई गोल्ड खरीदा जाना पाया गया जिस पर से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान में आये साक्ष्य एवं आरोपीगण से पूछताछ मे ज्ञात हुआ कि आरोपी कमल कुमावत आईसीआईसीआई विनवे वल्ड ऑफिस विजयनगर में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्य करता था, विभिन्न शहरो से कस्टमर के कॉल आने पर उनकी समस्याओं का निवारण करने का कार्य आरोपी कमल करता था, कार्य के दौरान आरोपी कमल को आईसीआईसीआई बैंक के आई. व्यु सॉफ्टवेयर में कस्टमर्स के खातो के ट्रांजेक्शन्स के ओटीपी जाते दिखाई दिये तब आरोपी के मन में लालच आ गया और कुछ दिन बाद आईसीआईसीआई विनवे वल्ड ऑफिस कार्य के दौरान आरोपी कमल कुमावत ने एक करंट अकाउंट में अच्छा वैलेंस देखकर आईसीआईसीआई कस्टमर का यूजर आईडी देखकर अपने मोबाइल फोन में आईसीआईसीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग द्वारा बैंकिंग सर्वर से पासवर्ड रिसेट के लिये ओटीपी कस्टमर को भेजा गया जो आरोपी कमल कुमावत को बैंक के आई. व्यु सॉफ्टवेयर में दिखाई दिया। उक्त ओटीपी का उपयोग कर आरोपी कमल ने उक्त करंट अकाउंट में लॉगइन कर लिया और अपना पर्सनल लोन खाते में एक लाख रूपये करीब ट्रांसफर कर सक्सेसफुली लोन क्लोज कर लिया। तब आरोपी के हौसले और बढ गये और आरोपी ने अपने साथ काम करने वाले सहकर्मी अभिषेक मालवीय एवं आईसीआईसीआई बैंक मनासा में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्य करने वाले अपने जीजा स्टेनली जैकब को शामिल करते हुये पूर्ण प्लानिंग के साथ सर्वप्रथम तेलंगाना के कागजनगर से तेलंगाना सर्कल की अन्य व्यक्तियों के नाम की फर्जी सिमे क्रय कराई और उक्त सिम के मो.न. का इस्तेमाल कर तीनो आरोपीगण ने अपनी नई ईमेल आई.डी. बनाई और अमेजन साईट पर अकाउंट बनाकर तनिश्क एप डाउनलोड किये, फिर आरोपी कमल कुमावत पूर्वानुसार काम के दौरान कस्टमर्स के करंट अकाउंट में बैलेंस देखकर अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज कर देता था और फिर अभिषेक और स्टेनली को उक्त चेंज किये पासवर्ड बताकर सभी के अमेजन अकाउंट्स से लाखों रूपये के गिफ्ट वाउचर पर्चेज कर कस्टमर का खाता खाली कर देते थे। आरोपीगण ने दर्जनो अकाउंट से कई बार धोखाधड़ीपूर्वक धनराशी की लगातार चोरी करते हुये मंहगें आईफोन 16 प्रोमैक्स, सैमसंग अल्ट्रा एस 24, सैमसंग जेड फ्लिप 6, एप्पल वॉच, सैमसंग अल्ट्रा वाच और भी कई इलेक्ट्रानिक आईटम लिये तथा तनिश्क एप में ईगोल्ड खरीदकर खरीदे हुये ईगोल्ड को विक्रय कर अपने पर्सनल अकाउंट्स में विक्रयधन प्राप्त किया, जब खाताधारकों द्वारा शिकायते की गई तब आरोपी कमल ने पकडे जाने से बचने के लिये पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से तेलंगाना से लाई गई सिम को तेलंगाना में नष्ट करने के लिये अपने पडोस में रहने वाले मित्र लवदीप को सैमसंग एस 24 अल्ट्रा देने का वादा करके प्लाईट से तेलंगाना भेजा तब लवदीप ने तेलंगाना जाकर सभी सिम कार्ड को मोबाइल फोन में डाला जिससे सभी सिमकार्ड की लोकेशन पुलिस को तेलंगाना मिले और फिर सभी सिमकार्ड नहीं नष्ट कर प्लाईट से वापस इंदौर आ गया। आरोपीगण का मकसद पुलिस को गुमराह करने का ही था। पुलिस कार्यवाही, प्रांरभ में पुलिस टीम को यही लग रहा था कि सिमकार्ड तेलंगाना में बंद हुये है संभवत: फ्रॉड करने वाला मुख्य सरगना तेलंगाना में होगा, किंतु पुलिस टीम ने बारिकी से अनुसंधान एवं तकनीकि साक्ष्य के लगातार विश्लेषण से सभी आरोपी ज्ञात किये और पृथक पृथक पुलिस टीम तेलंगाना, मनासा मंदसौर व इंदौर शहर में भेजकर सभी आरोपीगण को एक साथ गिरफ्तार किया। आरोपी कमल कुमावत, अभिषेक मालवीय, स्टेनली जैकब, लवदीप सिंह, कृष्ण कुमार ठाकुर एवं प्वाईन्ट ऑफ सेल वाले लिंक सिम विक्रेता को गिरफ्तार किया। आरोपियों से अत्याधिक महंगे आईफोन 16 प्रोमैक्स, सैमसंग एस 24 अल्ट्रा, जेड फ्लिप 6 आदि कुल 15 मोबाइल फोन, आईफोन, सैमसंग स्मार्ट वाच, गेम प्ले स्टेशन सहित करीब 19,74,500 रूपये के इलेक्ट्रानिक आईटम जब्त किये गये है। पीडित खाताधारकों के खातों में करीब 52 लाख रूपये की धनराशी भी वापस कराई गई है।

सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन, इंदौर संभाग में जारी अधोसंरचनात्मक
कार्यों की प्रगति की प्रत्येक 15 दिन में हो समीक्षा : सीएम डॉ. यादव

● विलंब के कारणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाएं ● प्रयागराज कुंभ प्रबंधन में क्रॉउड मैनेजमेंट, ड्रोन-सर्वे, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस क्षेत्र में हुए नवाचारों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का सिंहस्थ में होगा क्रियान्वयन ● इंदौर के लाल बाग पैलेस और दरबार हॉल राजवाड़ा तथा ओंकारेश्वर में ममलेश्वर मंदिर कॉम्प्लेक्स का भी होगा अनुरक्षण और विकास

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ-2028 में उज्जैन और इंदौर संभाग गतिविधियों के मुख्य केंद्र रहेंगे। इन संभागों में 2 ज्योतिर्लिंग होने से श्रद्धालुओं का आवागमन तथा धार्मिक गतिविधियां तुलनात्मक रूप से अधिक होंगी। इंदौर-उज्जैन संभाग में जारी विभिन्न विभागों के कार्य समय-सीमा में पूर्ण हों, यह मॉनिटरिंग प्रत्येक 15 दिन में सुनिश्चित करें। सक्षम स्तर के अधिकारी बैठक कर, कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें। ऐसे विषय जिन में उच्च स्तर से समन्वय या मार्गदर्शन आवश्यक है, वे विषय राज्य शासन के संज्ञान में लाए जाएं। निर्माण एजेंसियों को सौंपे गए कार्यों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित कर विलंब के कारणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय भोपाल में हुई सिंहस्थ-2028 की मंत्रि-मंडलीय समिति की द्वितीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उज्जैन तथा इंदौर जिलों में नवीन बस अड्डों के विकास के दिए निर्देशः मुख्यमंत्री ने कहा कि अधोसंरचना से संबंधित जिन कार्यों के निर्माण में अधिक समय लगना है, उन सब की मंत्रि-मंडलीय समिति से स्वीकृति प्राप्त करने और निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने का कार्य मार्च-2025 तक कर लिया जाए। जल प्रदाय, सीवरेज के कार्य तत्काल आरंभ किए जाएं। इसके साथ ही उज्जैन तथा इंदौर जिलों में बस अड्डों की क्षमता वृद्धि या नवीन बस अड्डों के विकास की कार्य योजना भी मार्च-2025 तक तैयार की जाए। सिंहस्थ-2028 के लिए समस्त विभागों के अधोसंरचनात्मक कार्यों की कार्य-योजना को सितंबर-2025 तक अंतिम रूप दिया जाए।

प्रयागराज कुंभ के साथ ही हरिद्वार कुंभ मॉडल का भी होगा अध्ययनः सीएम ने कहा कि सिंहस्थ-2028 की व्यवस्थाओं को श्रेष्ठतम स्वरूप देने के लिए प्रयागराज कुंभ के साथ ही हरिद्वार कुंभ मॉडल का अध्ययन भी किया जाएगा। प्रयागराज कुंभ पूर्ण होने के बाद वहां क्रॉउड मैनेजमेंट, ड्रोन सर्वे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग तथा अन्य गतिविधियों में लगी कंपनियों व स्टार्ट-अप का उज्जैन में सम्मेलन आयोजित कर वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस का क्रियान्वयन सिंहस्थ-2028 में करने की कार्य योजना बनाई जाएगी।

रेलवे से समन्वय के लिए विशेष सेल गठित किया जाएः उन्होंने श्रद्धालुओं के आवागमन में सुगमता के लिए रेलवे से समन्वय के उद्देश्य से विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाटों तक श्रद्धालुओं के आसानी से आवागमन के लिए उपयुक्त पहुंच मार्ग विकसित किए जाएं। उज्जैन, इंदौर और देवास में होने वाले निर्माण कार्यों में सीवरेज, स्वच्छता और हरियाली का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पर्यटकों की सुविधा की दृष्टि से धर्मशालाओं के उन्नयन के लिए भी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 को देखते हुए, आवश्यकतानुसार विभागों में प्रशासकीय संरचनाओं का विस्तार तत्काल किया जाए।

सिंहस्थ, सदियों पुरानी सनातन परम्परा को जीवंत करने का उत्सव - मंत्री विजयवर्गीयः नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सिंहस्थ, सदियों पुरानी सनातन परम्परा को जीवंत करने का उत्सव है। सिंहस्थ-2028 में पधार रहे श्रद्धालुओं के आवागमन और उनकी सुविधाजनक आवास व्यवस्था के लिए इंदौर, उज्जैन और देवास क्षेत्र में समन्वित रूप से व्यवस्थाएं विकसित की जाएं।

क्षिप्रा नदी में निरंतर जल प्रवाह के लिए जारी है कार्यः बैठक में जानकारी दी गई कि मंत्रि-मंडलीय समिति द्वारा प्रथम बैठक में जल संसाधन, ऊर्जा, लोक निर्माण, संस्कृति, पुरातत्व और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लगभग 5 हजार 955 करोड़ रूपए लागत के 19 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। बैठक में क्षिप्रा नदी में निरंतर जल प्रवाह के लिए संचालित योजना सहित क्षिप्रा व कान्ह नदी पर प्रस्तावित बैराजों के निर्माण, कान्ह नदी डायवर्शन और घाट निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही महाकाल लोक कॉरीडोर में पाषाण प्रतिमाओं के निर्माण, इंदौर-उज्जैन मार्ग के सिक्स लेन में चौड़ीकरण कार्य सहित उज्जैन के महत्वपूर्ण मार्गों, उज्जैन शहर की सीवरेज परियोजना आदि का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

कई विभागों के कार्यों को मिली स्वीकृतिः मंत्रि-मंडलीय समिति ने गृह, पर्यटन, संस्कृति तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के एक हजार 451 करोड़ रूपए लागत के 56 कार्य को स्वीकृति प्रदान की। इनमें गृह विभाग के अंतर्गत निर्मित होने वाले कंपोजिट कंट्रोल रूम उज्जैन, नवीन थाना भवन, इंटीग्रेटेड कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर खण्डवा सहित उज्जैन, खण्डवा, देवास, इंदौर, आगर-मालवा, खरगोन में बनने वाले पुलिस आवास, थाना, ट्रांजिट हॉस्टल व कैम्प, बैरक आदि शामिल हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सिंहस्थ के दौरान आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 5 सड़कों के चौड़ीकरण कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

महेश्वर में नर्मदा रिसोर्ट, ओंकारेश्वर में नवीन होटल, मंदसौर में पर्यटन सुविधा केन्द्र भी होंगे विकसितः मंत्रि-मंडलीय समिति ने पर्यटन विभाग के अंतर्गत उज्जैन में होटल महाराजबाड़ा द हेरिटेज, ग्रांड होटल, क्षिप्रा रेसीडेंसी तथा होटल उज्जैयिनी के उन्नयन, मंदसौर में पर्यटन सुविधा केन्द्र के उन्नयन और ओंकारेश्वर सर्किट विकास के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर और महेश्वर में यात्री सुविधाओं के विकास को स्वीकृति प्रदान की गई। नर्मदा रिसोर्ट महेश्वर, चोरल रिसोर्ट इंदौर, ओंकारेश्वर में नवीन होटल निर्माण और उज्जैन के होटल अवंतिका के उन्नयन कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। संस्कृति विभाग के अंतर्गत लाल बाग पैलेस परिसर इंदौर के उन्नयन, दरबार हॉल राजबाड़ा इंदौर के अनुरक्षण और विकास कार्य, ओंकारेश्वर स्थित ममलेश्वर मंदिर कॉम्पलेक्स के विकास और वीर दुर्गादास जी की उज्जैन स्थित छतरी के विकास और अनुरक्षण कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, संस्कृति, पर्यटन धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्यमंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री गौतम टेटवाल, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, मुख्य सचिव अनुराग जैन तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को अपने गौरव के अनुरूप नये स्वरूप में स्थापित किया जाएगा

● एक नया भवन बनेगा, नये पाठ्यक्रम शुरू होंगे, फैकल्टी की नई भर्ती भी होंगी

● संभागायुक्त सिंह की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न

इंदौर। श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को अपने गौरव के अनुरूप नये स्वरूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार कर कार्य कराये जाएंगे। महाविद्यालय का नया भवन बनाया जाएगा। इसमें सभी एकेडमिक और प्रशासनिक सुविधाएं रहेंगी।

महाविद्यालय में नये पाठ्यक्रम भी शुरू किये जाएंगे। फैकल्टी की नई भर्ती भी की जाएगी। यह जानकारी आज यहां संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई श्री वैष्णव सहायक कपड़ा मार्केट टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी की 59वीं बैठक में दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा, अध्यक्ष प्रबंध समिति पुरूषोत्तम दास पसारी, प्रभारी प्राचार्य एस.एस. शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। बैठक में इंदौर के श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के संचालन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि इस संस्थान का भवन भी पुराना हो गया है। फैकल्टी भी कम हो गई है। सुविधाएं भी धीरे-धीरे कम हो रही हैं। इन सबके मद्देनजर इस संस्थान की निर्धारित सीटों में भी कमी की गई है। संस्थान की साख भी कम होती जा रही है। संभागायुक्त दीपक सिंह ने समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नया भवन बनाया जाए।

संभागायुक्त दीपक सिंह ने पूर्नघनत्वीकरण योजना के तहत प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में श्री वैष्णव कपड़ा मार्केट ट्रस्ट के सहयोग से नये स्व-वित्त पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाए। सीटों की संख्या बढ़वाई जाए। नई फैकल्टी की नियुक्ति भी की जाए। महाविद्यालय के अक्षम फैकल्टी तथा कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव तैयार कराये जाए। यह सेवानिवृत्ति सामान्य प्रशासन विभाग के सेवा काल के 20 वर्ष तथा आयु के 50 वर्ष के निर्धारित नियमानुसार तैयार किये जाए। उन्होंने महाविद्यालय की कार्यप्रणाली में तेजी से सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की साख को पुनः स्थापित किया जाए। उन्होंने महाविद्यालय के एक व्याख्याता परेश सांवलिया के विरूद्ध लम्बे समय से लंबित कदाचरण की जांच को एक माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर एक माह में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर जांच समिति के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि महाविद्यालय में यह सुनिश्चित किया जाए कि पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट के अनुरूप दाखिला हो। सीट रिक्त रहने पर संबंधित पाठ्यक्रम के विभागाध्यक्ष और फैकल्टी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 2047 को दृष्टिगत रखते हुए तैयार होंगे विजन डॉक्यूमेंट

जिला पंचायत सभागृह में विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लिए ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ हुआ जन संवाद कार्यक्रम

इंदौर। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर आशीष सिंह के मार्गदर्शन में वर्ष 2047 को दृष्टिगत रखते हुए जिले एवं नगर के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर तक विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार होंगे। यह विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में जन संवाद कार्यक्रमों को आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त संवाद कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रीना मालवीय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भारत सिंह पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन सहित जिले के समस्त जनपदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, प्रत्येक जनपद से 5-5 सरपंच, महिला स्व सहायता समूह सदस्य, स्वच्छाग्रही, उन्नत कृषक, युवा व समस्त जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा समस्त विभागीय जिला अधिकारी शामिल हुए। इस जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन द्वारा मध्यप्रदेश के सर्वांगीण और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर होने एवं वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ-साथ मध्य प्रदेश को भी विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित मध्यप्रदेश 2047 विजन डाक्यूमेंट व इन्दौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण कार्यशाला की रूप रेखा व अवधारणा से उपस्थित प्रतिभागियों को विस्तार से अवगत कराया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में आम ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जाने के साथ-साथ जिला स्तर पर भी सम्पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु समस्त हितधारकों के साथ उक्त कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला के माध्यम से प्राप्त हुई आम ग्रामीणों की आकांक्षाओं, विचारों और प्राथमिकताओं को विजन डॉक्यूमेंट में सम्मिलित किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालवीय ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2047 तक अपना देश विकसित देशों की श्रेणी में अग्रणी रूप से शामिल हो। प्रधानमंत्री जी के इस सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र भी इस विकास यात्रा में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि गांव विकसित होगा तो प्रदेश विकसित होगा। प्रदेश विकसित होगा तो देश भी विकसित बनेगा। हम इंदौर ग्रामीण क्षेत्र में शासन की समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन व समाज के समस्त वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष पटेल ने अपने उद्बोधन में ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों व विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए इस आयोजित कार्यशाला की सार्थकता को उचित बताते हुए समाज के वंचित वर्गों के उत्थान पर जोर दिया व ग्रामीण क्षेत्रों में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने व कृषकों की समस्याओं को ध्यान में रखते कार्य योजना बनाने हेतु अपने सुझाव दिये। कार्यशाला में उपस्थित जिला पंचायत सदस्यों द्वारा भी विकसित ग्रामीण क्षेत्र इन्दौर को दृष्टिगत रखते हुए अपने सुझाव दिये गए। कार्यशाला में उपस्थित महिला समूह सदस्यों द्वारा भी महिला उत्थान, घरेलू हिंसा रोकथाम व महिला जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझाव दिये गए। कार्यशाला में उपस्थित कृषकों द्वारा उन्नत व जैविक खेती को बढाने एवं फसलों की उचित विपणन के संबंध में विस्तार से अपने सुझाव प्रस्तुत किये गए। उपस्थित युवाओं द्वारा भी भविष्य के भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका व युवाओं में बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्ति व नशाखोरी को रोकने हेतु अपने विचार साझा किये गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने कार्यशाला के दौरान बताया कि इन जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से फीडबैक संकलित कर राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। तैयार किए जा रहे विकसित मध्य प्रदेश 2047 के विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप को जिलों के साथ साझा किया जाएगा। इस प्रारूप के आधार पर प्रत्येक जिला मध्यप्रदेश के समग्र विजन के साथ संरेखित अपना जिला स्तरीय विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर सकेगा। यह प्रक्रिया जिलों की विशेषताओं, प्राथमिकताओं और संभावनाओं को शामिल करते हुए समग्र और समावेशी विकास सुनिश्चित करेगी।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग द्वारा एक लाख 69 हजार 609 पेंशनर्स हितग्राहियों को 7123.58 लाख रुपये दिये गये

इंदौर। जिले में बीते वर्ष एक लाख 69 हजार 609 हितग्राहियों को 7123.58 लाख रुपये की पेंशन उपलब्ध कराई गई। इंदौर जिले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इंदौर के संयुक्त संचालक द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के अंतर्गत बीते वर्ष की उपलब्धियों, भौतिक वित्तीय प्रगति के विषय में बताया गया है कि गत वर्ष 2024 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से 27 हजार 760 हितग्राहियों को 600 रुपये प्रतिमाह के हिसाब कुल 1165.92 लाख रुपये दिये गये।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 13 हजार 295 हितग्राहियों को 600 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 558.39 लाख रुपये प्रदत्त किये गये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना में 1205 हितग्राहियों को 600 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से रूपये 50.61 लाख रुपये प्रदत्त किये गये। कन्या अभिभावक पेंशन योजना के 4244 हितग्राहियों को 600 रुपये के हिसाब से 178.248 लाख रुपये दिये गये। मंदबुद्धि/बहुविकलांग आर्थिक सहायता में 600 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 2881 हितग्राहियों को रूपये 121.002 लाख रुपये प्रदत्त किये गये। समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना में 600 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 39 हजार 734 हितग्राहियों को 1668.828 लाख रुपये दिये गये। सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना में 600 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 648 हितग्राहियों को 27.216 लाख रुपये दिये गये। सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना में 600 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 10 हजार 580 हितग्राहियों को 444.36 लाख रुपये प्रदत्त किये गये।

सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 600 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 2133 हितग्राहियों को 89.586 लाख रुपये दिये गये। सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना में 600 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 66 हजार 855 हितग्राहियों को 2807.91 लाख रुपये दिये गये। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में 600 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 274 हितग्राहियों को 11.508 लाख रुपये दिये गये। कुल पेंशनर्स हितग्राही एक लाख 69 हजार 609 थे, जिन्हें 7123.58 लाख रुपये प्रदत्त किये गये। इसी प्रकार राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में 20 हजार रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 225 हितग्राहियों को 45 लाख रुपये दिये गये। मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना में एक लाख रुपये एवं दो लाख रुपये के हिसाब से 10 हितग्राहियों को 16 लाख रुपये प्रदत्त किये गए। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना में दो लाख रूपये के हिसाब से पाँच हितग्राहियों को 10 लाख रुपये दिये गये। कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरण योजना में 89 हितग्राहियों को 28 लाख रुपये दिये गये।

शीत लहर के प्रभाव से बचने के लिए बरते सावधानी, स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की

इंदौर। शीत लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। जारी एडवाइजरी में नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे सर्दी को देखते हुए विशेष सावधानी बरते। गर्म कपड़े पहने, जैसे फ्लू, सर्दी, खांसी एवं जुकाम आदि के लक्षण हो जाने पर चिकित्सक से संपर्क करें। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.एल. सोढ़ी ने बताया कि सर्दी के मौसम में जब ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगती है, तापमान में तेजी से गिरावट होने लगती है, तब इस स्थिति को शीत लहर कहते है, आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि सर्दी के मौसम में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 04-05 डिग्री नीचे चला जाता है तो इसे शीत लहर कहा जाता है। स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के लिए रेडियो, टी.वी. एवं समाचार पत्र जैसे सभी मीडिया द्वारा दी जा रही जानकारी का अनुसरण करें। पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े पहने। नियमित रूप से गर्म पेय पीते रहे। शीतलहर के समय विभिन्न प्रकार की बीमारियों की संभावना अधिक बढ़ जाती है, जैसे फ्लू, सर्दी, खांसी एवं जुकाम आदि के लक्षण हो जाने पर चिकित्सक से संपर्क करें। कम तापमान के लक्षण जैसे सामान्य से कम शरीर का तापमान, न रुकने वाली कपकपी, याददाश्त चले जाना, बेहोशी या मूर्छा की अवस्था का होना, जुबान का लड़खडाना आदि प्रकट होने पर चिकित्सक से संपर्क कर उपचार प्राप्त करें।

शीत लहर के दौरान सावधानियां बरतेः पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े जैसे दस्ताने, टोपी, मफलर, एवं जूते आदि पहने, शीतलहर के समय चुस्त कपड़े ना पहने यह रक्त संचार को कम करते है, इसलिये हल्के ढीले-ढालें एवं सूती कपड़े बाहर की तरफ एवं ऊनी कपड़े अंदर की तरफ पहने, शीतलहर के समय जितना संभव हो सके घर के अंदर ही रहें और कोशिश करें कि अति आवश्यक हो, तो ही बाहर यात्रा करें। पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों से युक्त भोजन ग्रहण करें एवं शरीर की प्रतिरक्षा बनाए रखने के लिए विटामिन-सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं एवं नियमित रूप से गर्म तरह पदार्थ अवश्य पीयें, आवश्यकतानुसार अनुसार रूम हीटर का उपयोग करें एवं रूम हीटर के प्रयोग के दौरान पर्याप्त हवा निकासी का प्रबंध करें, शीतलहर में अधिक ठंड के लम्बे समय तक संपर्क में रहने से त्वचा कठोर एवं सुन्न कर सकती है। शरीर के अंगों जैसे हाथ-पैर की उंगलियों, नाक एवं कान में लाल फफोले हो सकते है। शरीर के भाग के मृत हो जाने पर त्वचा का लाल रंग बदलकर काला हो सकता है। यह बहुत खतरनाक है और गैंग्रीन रोग कहा जाता है। इसके लिए तत्काल चिकित्सक से परामर्श ले।

'लालच बुरी बला है' रिटायर्ड अधिकारी से करोड़ों की धोखाधड़ी

इंदौर। इंदौर में साइबर अपराधियों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर बीएसएनएल के रिटायर्ड अधिकारी से 1 करोड़ 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। इस मामले में रिटायर्ड अधिकारी को लालच देकर पैसे निवेश कराए गए और फर्जी ऐप के माध्यम से रकम को कई गुना बढ़ा हुआ दिखाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद साइबर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए फरियादी को 25 लाख रुपए की राशि वापस दिला दी है। क्या है पूरा मामला मध्य प्रदेश में साइबर अपराध के नए और पुराने तरीकों से लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले को लेकर क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि, बीएसएनएल के रिटायर्ड अधिकारी को ईशानी मेहता नाम की एक महिला ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क किया। इसके बाद महिला ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का लालच देकर उन्हें एक अन्य व्यक्ति से बातचीत कराई और डिमैट अकाउंट खुलवाने का सुझाव दिया। इसके बाद व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजी गई, जिससे एक फर्जी ऐप डाउनलोड कराया गया। इस ऐप में अधिकारी द्वारा शुरू में किए गए 5000 रुपए के निवेश को 25,000 रुपए दिखाया गया। जब अधिकारी को विश्वास हो गया, तो उन्होंने 1 करोड़ 4 लाख रुपए निवेश कर दिए। ऐप में उनकी रकम को 9 करोड़ रुपए से अधिक दिखाया गया। लेकिन जब उन्होंने इस राशि को निकालने का प्रयास किया, तो उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। जिसके बाद उन्होंने साइबर अपराध की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया और शिकायत दर्ज कराई। साइबर अधिकारियों का कहना है कि 2024 इंदौर में साइबर अपराध हुए थे उसमें 65 करोड़ के अपराध इसी आधार पर हुए थे। अभी फिलहाल रिटायर बीएसएनल अधिकारी द्वारा जो रुपए ट्रांसफर बैंक खातों में किए गए थे। उनमें से तमाम बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही 25 लाख रुपए की राशि भी वापस फरियादी को करवाई जा चुकी है। अभी फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है।

Madhya Pradesh: Despite 80% Increase In Education Budget, Schools Struggle With Basic Facilities

In Madhya Pradesh, the government has increased expenditure on school education by 80% over the last seven years, raising the budget from Rs 16,226.08 crore in 2016-17 to Rs 29,468.03 crore in 2023-24. However, this significant financial boost has not translated into improved conditions in many government schools, which continue to grapple with a lack of basic infrastructure and facilities.

At the Government Secondary School in Khajuri Kalan, Bhopal, students face unsafe and unsanitary conditions daily. The school, which offers education up to Class 8, is in a dilapidated state. Classes are held in a tin shed with damp walls adorned with alphabet charts, while the roof leaks during rains. Toilets are unusable, and drinking water is unavailable.

Mansi Yadav, a student, shared her fear: "Once the roof fell on our madam. I am afraid that the roof may fall again, and I cannot focus on my studies." Another student, Madhu Yadav, expressed concern: "There is a lot of dirt. Water comes in from the windows, and our books get wet." Despite repeated complaints to the administration, the situation remains unchanged, highlighting the gap between government spending and ground realities.

The 2023-24 UDISE report paints a troubling picture of school infrastructure in the state: 13,198 schools rely on just one teacher. 3,620 schools lack separate toilets for girls. Toilets in 10,702 schools are non-functional. 7,966 schools lack handwashing facilities. 7,422 schools do not have access to drinking water. These deficiencies severely impact the learning environment, particularly for girl students, leading to hygiene concerns and further dropout rates.

Contradicting the increased budget allocation, government schools in Madhya Pradesh have witnessed a drastic decline in student enrollment. According to information presented in the state assembly, over 12 lakh students left government schools between 2016 and 2024: 6,35,434 students dropped out from Classes 1 to 5. 4,83,171 students left Classes 6 to 8. 1,04,479 students dropped out from Classes 9 to 12.

School Education Minister cited factors such as population decline in the 0-6 age group, improved data tracking, and dropout rates as reasons for this decline. However, opposition leaders argue that the grim state of schools is pushing students away.

Congress MLA Pratap Grewal questioned the effectiveness of the increased budget: "The government has increased the budget by 80%, yet children are losing interest in schools. Where is the money going?" He highlighted the dire conditions in schools as a pressing concern.

Responding to the criticism, BJP spokesperson Ajay Dhawale defended the government's efforts: "The Congress, which destroyed the education system during its rule, cannot question us. The BJP government is committed to improving education, as seen with the establishment of CM Rise Raj Schools." While the government claims to prioritise education, the reality is starkly different for students and teachers in many parts of Madhya Pradesh. The lack of functional toilets, clean drinking water, and safe infrastructure continues to plague schools. These conditions raise serious questions about the effective utilisation of the increased education budget and its impact on the state's future generations.

National Eligibility Test No More Mandatory For Assistant Professor Post

The University Grants Commission (UGC) has released a draft of the minimum qualifications for the appointment and promotion of teachers and academic staff in universities and colleges, as well as measures for the maintenance of standards in higher education. Stakeholders are requested to submit feedback on the draft regulations by February 5, 2025.

As per the regulations, the UGC has recommended the removal of the National Eligibility Test (NET) as a requirement for the appointment of assistant professor and promotions in higher education institutions. As per the proposal, candidates having a postgraduate degree in ME or MTech with at least 55 per cent marks will be eligible for the post of assistant professor (entry level post). Currently, UGC-NET exam is the mandatory requirement for the eligibility of assistant professor. Besides this, candidates with an undergraduate degree (NCrF Level 6) with at least 75 per cent marks or a PG degree (NCrF Level 6.5) with at least 55 per cent marks (or an equivalent grade) and a PhD degree (NCrF Level 8) are eligible for the post of assistant professor. Other eligibility includes a PG degree (NCrF Level 6.5) with at least 55 per cent marks (or an equivalent grade) and qualification in the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR, ICAR etc or a similar test like SLET/SET.

The new regulations also change the selection process of vice chancellors, such as expanding eligibility criteria to include professionals from academia, research institutions, public policy, public administration, and industry. According to the guidelines, the selection for the vice chancellor's post will be through an all-India newspaper advertisement and public notification. Applications can also be sought through nomination or a talent search process by a Search-cum-Selection Committee. These regulations also provide clear guidelines on the composition of the VC's search-cum-selection committee, tenure, age limits, eligibility for reappointment, and who can form the search-cum-selection committee.

The guidelines further mention the appointment of a principal. According to the new guidelines a principal would be appointed for a period of five years, with eligibility for reappointment for one more term by following the procedure prescribed for selection of the principal. However, she/he can serve as a principal for only two terms in the same college. After completing the terms as principal, the incumbent will rejoin his parent organisation with the designation of professor and in the professor grade, provided he/she fulfills the eligibility criteria for professor.

IIT-Delhi launches certificate programmes in Finance, Supply Chain, and Semiconductor Technology

The Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi) has introduced three new certificate programmes under its Continuing Education Programme (CEP) in collaboration with TeamLease Edtech. These short programmes will be conducted through live, interactive online sessions in a Direct-to-Device (D2D) format, incorporating industry-relevant case studies and assignments. These three courses introduced by IIT Delhi are released:

— The Chief Financial Officer Programme:

Any graduate or diploma holder with a minimum of 8 years of experience is eligible for the course. The deadline for the course is January 31 with a fee of Rs 4,13,000 (3,50,000 + 18% GST which can be paid in 3 installments of 1.5L, 1L, 1L).

—The Executive Management Programme in Supply Chain and Operations Analytics:

Any candidate with a bachelor's degree is eligible for the job application. The application will be closed on February 7 with a fee structure of Rs 1,41,600 (1,20,000 + 18% GST which can be paid in 2 instalments of 60k).

—The Executive Programme in Semiconductor Manufacturing and Technology:

Candidates who are interested in this programme must possess BTech, MSc, 10+2+3 diploma holders. The application has been started and will end on March 23. The fee structure of the course is Rs 1,47,500 (1,25,000 + 18% GST which can be paid in 2 instalments of 60k and 65k)

Additionally, the participants of the Chief Financial Officer programme and the executive programme in Semiconductor Manufacturing and Technology will have a two-day campus immersion. For more information, interested candidates can visit the official website of the Institute.

Students' body, teachers question new UGC draft regulation on faculty appointments

Left-leaning Students' Federation of India (SFI) has said in a statement on Tuesday (January 7, 2025) that it rejects the Draft University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment and Promotion of Teachers and Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2025, released on Monday. The SFI said the regulation was yet another attempt to "centralise and corporatise" campuses.

SFI leaders Mayukh Biswas and V.P. Sanu said the revised rules provided Governors with increased authority in the selection of Vice-Chancellors. "It is quite evident that the process of short-listing candidates for interview and final selection is very opaque: there's no clarity about whoever will be called," they said. They added that the draft, for the first time, allowed industry experts and public sector veterans to be considered for the role of Vice-Chancellors. "This marks a departure from the long-standing practice of exclusively appointing academicians and introduces corporate culture in academic arena. It will be a massive dilution of the quality of faculty by doing away with specialisation in a core discipline and the recruitment gives 100% weightage to the selection committee which is subjective in nature and does not give any credit to academic qualification, research publications and teaching experience," the SFI said.

Delhi University Teachers' Association Executive Committee member Rudrashish Chakraborty said in a response that the recruitment criteria endorsed the National Education Policy's emphasis on the common courses, which are poor and substandard. "The recruitment criteria shows a shift in focus from cutting edge research to merely reiterating existing knowledge: since core competence is done away with. There's no mention of the maximum hours to be put in for direct teaching in a week for teachers: a dangerous ploy to increase workload and to reduce jobs," he said.

Exam city slip soon at jeemain.nta.nic.in; exam pattern changes, admit card release date

The National Testing Agency (NTA) will soon release the Joint Entrance Examination (JEE) Main 2025 city intimation slip. Candidates will be able to download the JEE Main City intimation slip 2025 through the official website at jeemain.nta.nic.in. The JEE Main BTech exam will begin from January 22 to 30, 2025. Candidates will need their application number and password to download the JEE Main 2025 city slip According to the NTA schedule, the JEE Main 2025 exam for BTech will be held on January 22, 23, 24, 28, and 29, while the BArch exam will be conducted on January 30. The JEE Main 2025 admit card will be issued three days before the exam, that is, January 19, 2025.NTA revised the JEE Main 2025 exam pattern. As per the new changes, the section B will not include optional questions. Only five questions will be given and students will have to answer all five questions mandatorily. The JEE Main 2025 syllabus includes three subjects - physics, chemistry, and mathematics.The JEE Main 2025 city slip will include the city in which the candidate's exam centre will be allotted. Applicants were asked to enter four choices for cities while filling out the JEE Main application form.Candidates will have to carry the JEE Main 2025 admit card to the exam hall. The admit card will include details such as exam centre, date, timing, paper, roll number etc.

IGNOU launches BA programme in Micro, Small and Medium Enterprises

The Indira Gandhi National Open University (IGNOU) has introduced a Bachelor of Arts programme in Micro, Small, and Medium Enterprises (BAMSME). This programme will be offered through the School of Vocational Education and Training. It seeks to equip aspiring entrepreneurs with the skills, knowledge and confidence needed to launch and successfully manage business ventures. The BAMSME programme, beginning in the January 2025 academic session, is designed to address the evolving needs of young entrepreneurs in India. With a curriculum spread over three years and worth 120 credits, the programme is for students who have completed their 10+2 education. Delivered in English via the open and distance learning (ODL) mode, the IGNOU programme will offer flexibility and accessibility for learners across the country. The programme focuses on analysing market demand before launching a new venture, ensuring profitable business operations, and developing key managerial, interpersonal, and leadership skills, an official statement issued in this regard said. Additionally, the new programme will provide an innovative, competency-based approach to entrepreneurship, preparing students to lead and succeed in the competitive business world, it added.

Eligibility and programme details

– Qualification: Applicants must have completed 10+2 or its equivalent.

– Medium of Instruction: English.

– Duration: The programme spans 3 years, with a validity of up to 6 years.

– Session Availability: The programme is offered in two cycles – January and July.

– Fee Structure: Rs 5,100 per year (Total fee for 3 years = Rs 15,300).

Candidates interested in enrolling in the programme will have to visit the official IGNOU admissions portal – IGNOU admission portal to register.

अदाणी मामले को लेकर अमेरिकी सांसद ने उठाए सवाल, कहा- इससे भारत-अमेरिका के संबंध को नुकसान

नईदिल्ली, एजेंसी। भारतीय अरबपति गौतम अदाणी और उनकी कंपनियों के खिलाफ जांच के बाइडन प्रशासन के फैसले को लेकर रिपब्लिकन सांसद ने न्याय विभाग को घेरा है। सांसद ने कहा है कि ऐसी कार्रवाईयों से भारत-अमेरिका संबंधों को नुकसान हो सकता है। अमेरिकी अटार्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड को लिखे पत्र में सांसद लांस गुडेन ने कहा कि न्याय विभाग की ऐसी चुनिंदा कार्रवाईयों से अमेरिका के वैश्विक संबंध और आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है।

सदन न्यायपालिका समिति के सदस्य और सांसद लांस गुडेन ने पत्र लिखकर अमेरिकी अटार्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड से जवाब मांगा है। गुडेन ने अपने पत्र में पूछा कि यदि भारत प्रत्यर्पण अनुरोध का पालन करने से इनकार कर देता है तो अमेरिका क्या करेगा। उन्होंने न्याय विभाग द्वारा विदेशी इकाइयों के विरुद्ध किए गए अभियोजन के बारे में भी जवाब मांगा। उन्होंने पत्र में यह भी पूछा कि क्या इसका जॉर्ज सोरोस से कोई संबंध है

गुडेन ने कहा कि भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक है। न्याय विभाग को कमजोर अधिकार क्षेत्र वाले मामलों को आगे बढ़ाने, विदेशों में अफवाहों का पीछा करने के बजाय घरेलू स्तर पर बुरे लोगों को दंडित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सांसद ने कहा कि उन संस्थाओं को निशाना बनाना जो अरबों डॉलर का निवेश करती हैं और अमेरिकियों के लिए हजारों नौकरियां पैदा करती हैं, दीर्घकाल में अमेरिका को ही नुकसान पहुंचा सकता है।

उन्होंने कहा कि जब हम हिंसक अपराध, आर्थिक जासूसी से जुड़े खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं और उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं जो हमारे आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, तो यह हमारे देश में निवेश करने वाले मूल्यवान निवेशकों को हतोत्साहित करता है। ऐसा माहौल अमेरिका के औद्योगिक आधार और आर्थिक विकास के प्रयासों को रोक देगा। साथ ही बढ़ते निवेश के साथ अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिबद्धता को कमजोर करेगा।

गुडेन ने कहा कि इन फैसलों से साफ है कि बाइडन प्रशासन के अंत होने वाला है। इसका एकमात्र लक्ष्य राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मुश्किलें पैदा करना है। न्याय विभाग को अमेरिकी लोगों की सेवा करने के लिए आने वाले प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए। न्याय विभाग का कर्तव्य है कि आप ऐसी जटिलताएं पैदा न करें, जिससे अमेरिका की भू-राजनीतिक प्रतिष्ठा को खतरा हो।

उन्होंने कहा कि मैं न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा हाल ही में विदेशी संस्थाओं के खिलाफ चुनिंदा मामलों की जांच के बारे में पूछताछ करने के पत्र लिख रहा हूं। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में हमारा देश एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, अमेरिकियों को उम्मीद है कि यह समृद्धि, विकास, आर्थिक सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता के पुनरुद्धार का प्रतीक होगा। हमारे देश की समृद्धि को पुनर्जीवित करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कारक अमेरिका में व्यापार करने के लिए संभावित निवेशकों की क्षमता और स्वतंत्रता शामिल है।

उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर बढ़ते हिंसक अपराधों के बारे में जनता के आक्रोश को पूरी तरह दरकिनार करते हुए न्याय विभाग विदेशों में कथित अन्याय के लिए व्यवसायों को लक्षित करने के लिए नए अभियान चला रहा है।

सांसद ने अदाणी मामले को लेकर न्याय विभाग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अदाणी मामले में आरोप सच साबित हो जाएं, फिर भी हम इस मुद्दे पर उचित और अंतिम मध्यस्थ नहीं बन पाएंगे। ये रिश्वत कथित तौर पर भारत में भारतीय राज्य सरकार के अधिकारियों को एक भारतीय कंपनी के भारतीय अधिकारियों द्वारा दी गई थी, जिसमें किसी भी अमेरिकी पक्ष की कोई ठोस संलिप्तता या नुकसान नहीं था। इसके विपरीत अमेरिकी कंपनी स्मार्टमैटिक के अधिकारियों ने कथित तौर पर धन शोधन किया और विदेशी सरकारों को रिश्वत दी। यदि मामला संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण सांठगांठ से जुड़ा है, तो न्याय विभाग ने एक भी अमेरिकी पर अभियोग क्यों नहीं लगाया है

उन्होंने पूछा कि क्या इस योजना में कोई अमेरिकी शामिल नहीं था डीओजे ने गौतम अदाणी के खिलाफ ही मामला क्यों चलाया, जबकि कथित आपराधिक कृत्य और इसमें शामिल पक्ष भारत में हैं क्या आप भारत में न्याय लागू करना चाहते हैं क्या न्याय विभाग इस मामले में शामिल भारतीय अधिकारियों के प्रत्यर्पण की मांग करेगा अगर भारत प्रत्यर्पण अनुरोध का पालन करने से इनकार कर देता है और इस मामले पर एकमात्र अधिकार का दावा करता है, तो न्याय विभाग की आकस्मिक योजना क्या होगी क्या न्याय विभाग या बाइडन प्रशासन इस मामले को संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जैसे सहयोगी के बीच एक अंतरराष्ट्रीय घटना में बदलने के लिए तैयार है

अमेरिकी अभियोजकों ने अदाणी समूह पर क्या आरोप लगाए

अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अदाणी (62), उनके भतीजे सागर अदाणी और अन्य पर सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। अदाणी पर 2,029 करोड़ रुपये (265 मिलियन डॉलर) की रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। एक अनुमान के अनुसार इससे समूह को संभावित रूप से दो अरब डॉलर से अधिक का लाभ हो सकता है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि यह सब उन अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छुपाया गया, जिनसे अदाणी समूह ने इस परियोजना के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। कुछ रिपोर्ट्स में किए गए दावों के अनुसार, गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया।

चुनौतियों के बावजूद 2024 में वाहन बिक्री में 9 प्रतिशत उछाल, भीषण गर्मी-चुनाव और मानसून से जूझता रहा उद्योग

नईदिल्ली, एजेंसी। चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल के बीच दोपहिया और यात्री वाहनों की मजबूत मांग से 2024 में गाड़ियों की बिक्री में सालाना आधार पर 9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक,

कैलेंडर वर्ष 2024 में देशभर में कुल 2,61,07,679 वाहन बिके। 2023 में कुल 2,39,28,293 गाड़ियां बिकी थीं। फाडा के अध्यक्ष सी एस विग्नेश्वर ने कहा, 2024 में भीषण गर्मी, केंद्र एवं राज्यों में चुनाव और असमान मानसून सहित कई प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वाहन खुदरा उद्योग मजबूत बना रहा। संगठन के अध्यक्ष ने कहा, दोपहिया वाहन सेगमेंट में बेहतर आपूर्ति, नए मॉडल और मजबूत ग्रामीण मांग ने बिक्री में वृद्धि को बढ़ावा दिया। हालांकि, वित्तीय बाधाएं और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की लगातार बढ़ रही संख्या से चुनौती मिल रही है।इसके अलावा, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के बीच कीमतों को लेकर सतर्क रहने वाले ग्राहकों की धारणा पर भी नजर रखने की जरूरत है।

जमाना ऑनलाइन लर्निंग का

आज के दौर में आनलाइन लर्निंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। आप भी अपने पीसी या लैपटॉप के सामने बैठकर और इंटरनेट से जुड़कर पढना चाहते हैं, तो आनलाइन-लर्निंग एक बेस्ट आप्शन हो सकता है। कुछ बातों को ध्यान में रखकर ऑनलाइन पढाई कर सकते हैं। इससे आप कॉलेज में अटेंडेंस के चक्कर से भी बच जाएंगे। बस आपको ध्यान रखनी होगी डेट लाइन की। खास बात यह कि ऑनलाइन कोर्स के जरिए सर्टिफिकेट कोर्स का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

एलसीबीएस के फाउंडर एंव सीईओर अभय गुप्ता बताते हैं किसी भी विषय के कोर्स कितने महंगे होते जा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन कोर्स के शुरू होने से आज आप घर बैठे ही अपने मोबाईल या कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले कोर्स कर सकते हैं।

कोर्स का विवरण

एक महीने की अवधि वाले इस नए कोर्स ऑनलाइन लग्जरी मैनेजमेंट को शुरू करने का मुख्य कारण स्टूडेंट को लग्जरी मैट्रिक्स की जटिलताओं को आसानी से समझाना और लग्जरी के उद्योग में मंदी के दौर में भी स्टूडेंट्स के करियर को एक अच्छा ट्रैक देना है। वहीं दूसरे कोर्स एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन लग्जरी मैनेजमेंट जिसकी अवधि 6 महीने है, जिससे स्टूडेंट भारतीय लग्जरी उद्योग के अनुभवी विशेषज्ञों और यूरोप के लग्जरी एक्सपर्ट्स और प्रोफेसर द्वारा दुनिया भर में लग्जरी व्यापार के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण मिल रहा है। यह कोर्सेज युवाओं के लिए एक अच्छे करियर के रूप में बन सकते हैं।

योग्यता

इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए छात्र-छात्राओं का ग्रेजुएट होना जरुरी है। साथ ही स्टूडेंट की लग्जरी और मैनेजमेंट में दिलचस्पी भी होनी बेहद जरुरी होती है। इसके अलावा वो छात्र-छात्राएं जिनकी पर्सनालिटी और कम्यूनिकेशन स्किल्स अच्छी है और अंग्रेजी में अच्छी पकड़ है, वो इस क्षेत्र में एक सफल तौर पर अपना करियर बना सकते हैं। कोई एक विदेशी भाषा की जानकारी लाभदायक साबित हो सकती है पर यह अनिवार्य नहीं है।

अवसर

ऑनलाइन कोर्स इन लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन लग्जरी मैनेजमेंट कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स लग्जरी सेल्स एडवाइजर, मार्केटिंग मैनेजर, ब्रांड कंट्री हेड, विजुअल मर्चेडाइजर, लग्जरी इवेंट प्लानर, ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं। फैशन और लग्जरी कंसल्टेंट या वार्डरोब मैनेजर के तौर पर भी काम पा सकते हैं।

वेतन - इस कोर्स के पूरा होने के बाद स्टूडेंट्स लग्जरी की इंडस्ट्री में अलग-अलग कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें बतौर स्टा-इपेंड 20 से 22 हजार रुपए मिलते। अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो शुरूआती सैलरी प्रति माह 30,000 रु. से 40,000 रु. के बीच हो सकती है।

फोरेंसिक साइंस रोमांचकारी कॅरियर

फोरेंसिक साइंस एक अप्लाइड साइंस है। अपराधियों का पता लगाने के लिए इस में वैज्ञानिक सिद्धांतों व तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस कार्य में सहायक होते हैं अपराध स्थल से मिले साक्ष्य। आधुनिकता के साथ अपराध के तरीके बढ़े हैं, तो छानबीन के तरीके भी ईजाद हुए हैं। युवाओं का इस फील्ड के प्रति रुझान बढ़ा है।

देश में दिन प्रतिदिन अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। यदि देश का युवा चाहता है कि उसका देश, राज्य या शहर अपराधमुक्त हो तो उसे अवश्य ही फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में अपना कॅरियर बनाना चाहिए। युवाओं के लिए यह क्षेत्र अत्यंत ही रोमांचकारी एवं आह्वनात्मक है। इस क्षेत्र में युवा अपनी पहचान बनाकर नाम कमा सकते हैं। हमें युवाओं को सबसे पहले ये बताना होगा कि फोरेंसिक साइंस है क्या? और कैसे वह रोमांचकारी और आह्वनात्मक होता है। उदाहरणार्थ किसी घटनास्थल पर कोई वारदात होती है और वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी को पकड़ पाना आसान नहीं होता तो उसे घटना स्थल की छोटी से छोटी वस्तु को भी इस साइंस की प्रयोगशाला में जांचा परखा जा सकता है और अपराधी तक पहुंचा भी जा सकता है। अपराधी को सजा दिलाने के लिए गवाही की आवश्यकता होती है और कई बार घटनास्थल पर इसका होना संभव नहीं हो पाता ऐसी अवस्था में घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाने का प्रयत्न यह फोरेंसिक साइंस करता है। फोरेंसिक साइंस विज्ञान की ही एक व्यवहारिक शाखा है। इस सांइस के द्वारा अपराधी के शोध से संबंधित छोटी से छोटी वस्तु का भी परीक्षण प्रयोगशाला में कर अपराधी को तलाशने का प्रयास किया जाता है। इसमें आधुनिक तंत्र ज्ञान का वापर किया जाता है। घटनास्थल पर अपराधी जब घटना को अंजाम देता है तो उस वक्त वहां वह कोई न कोई वस्तु अवश्य छोड़ जाता है मसलन रक्त, शारीरिक द्रव्य, नाखून, बाल, हाथ या पैरों के निशान इत्यादि इन सबका परीक्षण फोरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला में किया जाता है और आरोपी तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

इस प्रकार इस विज्ञान का महत्व अपराध जगत के लिए बहुत अधिक समझा और जाना जाता है। इस क्षेत्र में दाखिल होने के लिए युवाओं को बारहवीं कक्षा में विज्ञान से संबंधित विषय लेने होते हैं। जब बारहवी उत्तीर्ण हो तो इस शाखा में प्रवेश लेकर उपाधि ग्रहण की जा सकती है। ऐसे युवा जिन्होंने उपाधि में विज्ञान से संबंधित विषय जैसे भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, जैविक रसायनशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, बीफार्मा, या बीडीएस को भी इस क्षेत्र में दाखिल होने के अवसर प्राप्त है। इस क्षेत्र में पुलिस विशेषज्ञ, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट, व इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर व पूरी न्याय संख्या से संबंधित पद होते हैं जिसमें दक्षता प्रमाणित करने व मान-प्रतिष्ठा मिलाने के लिए अपार संभावनाएं हैं। अपराध के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए निजी गुप्तचर भी फोरेंसिक साइंस वालों को अच्छा अवसर प्रदान करने लगे हैं। इस क्षेत्र में यदि युवा दाखिल होने का इच्छुक है तो उसे अनिवार्य योग्यता हासिल कर लेने के पश्चात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सफल होना आवश्यक होता है। उस परीक्षा में जो अभ्यार्थी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होते हैं उन्हें तुरंत नियुक्ति मिल जाती है।

चुनौतियों भरा

यह प्रोफेशन चुनौतियों भरा है। इसलिए इस करियर में आना है, तो चुनौतियों से निपटना आना चाहिए। किसी केस को निपटाने के लिए कभी-कभी असफलता भी हाथ लगती है, तो ऐसे में धैर्य नहीं खोना चाहिए और उस केस को चुनौती के तौर पर लेना चाहिए। जांच-पड़ताल का क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है कि दोस्त कम होंगे और दुश्मन ज्यादा बन जाएंगे, तो इस बात से भी भयभीत होने की चुनौती भी इस करियर में है। हर स्थिति से निपटने की चुनौती स्वीकार करने वाला ही इसमें सफल होता है।

वेतनमान

गवर्नमेंट संस्थान में नौकरी मिलने पर इस क्षेत्र में आरंभिक दौर में 20 हजार रुपए प्रतिमाह तक वेतन मिलता है। इस के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी इस जॉब में अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है।

देश में अनेक विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान इस फोरेंसिक साइंस के अभ्यासक्रम को संचालित करते हैं लेकिन उनमें कुछ चुनिंदा संस्थान है जहां से पास आउट विद्यार्थियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए बाजी मारी है।

संस्थाओं के नाम निम्नानुसार है-

- लोकनायक जय प्रकाश नायक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमीनालॉजी एंड फॉरेंसिकसाइंस दिल्ली।
- डॉ.हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मप्र।
- डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस पंजाब विद्यापीठ पंजाब।
- लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ उप्र।
- दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली युवा चाहें तो इस क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं।

लॉन्ड्री व्यवसाय में भी अच्छे अवसर

आज शहरों में अनेक आलीशान होस्टल्स, होटल और अनेक वसतीगृह खुल गए हैं जिससे लॉन्ड्री व्यवसाय को बल मिल रहा है। इस व्यवसाय को चलाने के लिए दूसरे अन्य व्यवसायों जैसी लागत भी नहीं लगती। इसका खर्च सहजता से किया जा सकता है। जगह के नाम पर 300 से 500 वर्गफीट की आवश्यकता होती है। मशीन का मूल्य तीन से पांच लाख रुपए होता है और कामगार के नाम पर 2 से 4 नौकर धुलाई के लिए रखे जा सकते हैं। कपड़ों की धुलाई को ध्यान में रखें तो इस मशीन से रोजाना सत्तर से सौ किलो कपड़े धोए जा सकते हैं। और रोजाना कमाई आठ से दस हजार रुपए अपेक्षित होती है।

एक जमाना था जब हम कपड़ों को धोने के लिए रजक, परीट या धोबी के भरोसे रहते थे, परन्तु आज इस इक्कीसवी सदी में कपड़ों की धुलाई के लिए मशीनें उपलब्ध हैं जिसे हम लॉन्ड्री व्यवसाय के नाम से जानते हैं। आज महानगरों में ही नहीं तो गांवों, शहरों में भागमभाग की जिन्दगी है। समय का अभाव है। ऐसे में उस व्यवसाय में कैरियर के लिए बहुत अच्छे चांसेस है।

आज जिस भारत को हम कृषिप्रधान देश के नाम से जानते थे। जिसकी 75 प्रतिशत आबादी गांवों में ही वास करती थी। उस भारत का सपाटे से शहरीकरण और व्यवसायीकरण हो रहा है और एक अनुमान के अनुसार, 2027 तक देश की कल 60 प्रतिशत जनता शहरों में बसेगी। ऐसे में इस व्ययसाय के रूप में आगे चलकर और भी वृहद होने वाला है। आज पति-पत्नी दोनों ही या तो नौकरी में हैं या व्यवसाय में। इसलिए कपड़ों की धुलाई प्राय- लॉन्ड्री में ही होती है। एक सर्वेक्षण से ये सत्य सामने आया है कि देश के तीन करोड़ श्रीमंत लोग अपनी धुलाई और आयरन के लिए लॉन्ड्री में देते हैं। औसतन यदि हम खर्च देखें तो एक परिवार का प्रति माह एक हजार रुपए कपड़े धुलाई और आयरन पर खर्च होता है। आज शहरों में अनेक आलीशान होस्टल्स, होटल और अनेक वसतीगृह खुल गए हैं जिससे लॉन्ड्री व्यवसाय को बल मिल रहा है। इस व्यवसाय को चलाने के लिए दूसरे अन्य व्यवसायों जैसी लागत भी नहीं लगती। इसका खर्च सहजता से किया जा सकता है। जगह के नाम पर 300 से 500 वर्गफीट की आवश्यकता होती है। मशीन का मूल्य तीन से पांच लाख रुपए होता है और कामगार के नाम पर 2 से 4 नौकर धुलाई के लिए रखे जा सकते हैं। कपड़ों की धुलाई को ध्यान में रखें तो इस मशीन से रोजाना सत्तर से सौ किलो कपड़े धोए जा सकते हैं। और रोजाना कमाई आठ से दस हजार रुपए अपेक्षित होती है।

इसका सबसे बड़ा ग्राहक रेल्वे है। उसके बाद बड़े-बड़े पाश हॉस्पिटल्स, होटल्स, स्कूल कॉलेजों के होस्टल्स और अनेक रईस परिवार हैं। धुलाई का कोई तोटा नहीं है कहें तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज की लॉन्ड्रियां पूरी तरह नई तकनीक से सुसज्जित है। इस तकनीक ने इस व्यवसाय को हाईटेक बना दिया है। आपको एक फोन करने या मोबाईल एप पर मैसेज डालने की आवश्यकता है कि कुछ ही क्षणों में लॉन्ड्री का पिकअप ब्वाय आपके घर के दरवाजे पर हाजिर होता है।

आपको ये सारे कपड़े धोकर आयरन चलाकर और एक आकर्षक पैकिंग के साथ आपके घर पहुंचाए जाते हैं। इसमें सिर्फ तीन की अवधि लगती है। कभी-कभी तो लॉंड्री के इस आकर्षक पैकिंग को देखकर तो ये भ्रम होने लगता है कि कहीं हमने नए कपड़ों की शॉपिंग तो नहीं की है। आज इस इक्कीसवीं सदी में मनुष्य का जीवन वेगवान है। भागमभाग की जिन्दगी में वह अपने कपड़ों की धुलाई और आयरन के लिए लॉन्ड्रियों पर ही निर्भर रहता है। आज शहर हो या गांव, महानगर की बात ही अलग है कोई भी व्यक्ति धोया कपड़ा बगैर आयरन के नहीं पहनता। आयरन कराना एक अनिवार्यता बन गई है। ऐसे में इस व्यवसाय से कोई भी मनुष्य इस लॉन्ड्री व्यवसाय से चालीस से पचास हजार तक का नफा कमाया जा सकता है। आप इस डिजिटल युग में इस व्यवसाय को किस तरीके से और कैसा बढ़ाया जाए ये उद्योजक पर निर्भर करता है। समय बदल गया है। तकनीक बदल गई। अब न तो परीट या रजक नजर आते और न ही धोबीघाट। आजकल इन सब का काम लॉन्ड्री व्यवसाय में वापरी जाने वाली आधुनिक मशीनें ही करती हैं।

कमाई का बढ़िया जरिया किचन गार्डन

साग-सब्जियों का हमारे दैनिक भोजन में महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर शाकाहारियों के जीवन में। आजकल लोगो को शुध्द सब्जी मिलना बहुत ही मुश्किल है इसलिए आप आपके घर के आंगन में, घर की छत पर या अगर आपके पास कोई जमीं है तो आप आसानी से सब्जी बगीचा (किचन गार्डन) बना सकते हैं, इससे आपको शुध्द सब्जियां भी मिलेंगी और साथ ही आप इन सब्जियों को बेच कर पैसे भी कमा सकते हैं !

साग-सब्जी भोजन में ऐसे पोषक तत्वों के स्रेत हैं, हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं बढ़ाते, बल्कि उसके स्वाद को भी बढ़ाते हैं। पोषाहार विशेषज्ञों के अनुसार संतुलित भोजन के लिए एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 85 ग्राम फल और 300 ग्राम साग-सब्जियों का सेवन करना चाहिए, परंतु हमारे देश में साग-सब्जियों का वर्तमान उत्पादन स्तर प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति की खपत के हिसाब से मात्र 120 ग्राम है। इसलिए हमें इनका उत्पादन बढ़ाना चाहिए।

सब्जी बगीचा के लिए स्थल चयन

सब्जी बगीचा के लिए स्थल चयन में सीमित विकल्प है। हमेशा अंतिम चयन घर का पिछवाड़ा ही होता है जिसे हम लोग बाड़ी भी कहते हैं। यह सुविधाजनक स्थान होता है क्योंकि परिवार के सदस्य खाली समय में साग-सब्जियों पर ध्यान दे सकते हैं तथा रसोईघर व स्नानघर से निकले पानी आसानी से सब्जी की क्यारी की ओर घुमाया जा सकता है। सब्जी बगीचा का आकार भूमि की उपलब्धता और व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। सब्जी बगीचा के आकार की कोई सीमा नहीं है परंतु सामान्य रूप से वर्ग की अपेक्षा समकोण बगीचा को पसंद किया जाता है। चार या पांच व्यक्ति वाले औसत परिवार के लिए 1/20 एकड़ जमीन पर की गई सब्जी की खेती पर्याप्त हो सकती है।

बनाएं सब्जी बगीचा

स्वच्छ जल के साथ रसोईघर एवं स्नानघर से निकले पानी का उपयोग कर घर के पिछवाड़े में उपयोगी साग-सब्जी उगाने की योजना बना सकते है। इससे एक तो एकित्रत अनुपयोगी जल का निष्पादन हो सकेगा और दूसरे उससे होने वाले प्रदूषण से भी मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही, सीमित क्षेत्र में साग-सब्जी उगाने से घरेलू आवश्यकता की पूर्ति भी हो सकेगी। सबसे अहम बात यह कि सब्जी उत्पादन में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने की जरूरत भी नहीं होगी। यह एक सुरिक्षत पद्धति है तथा उत्पादित साग-सब्जी कीटनाशक दवाईयों से भी मुक्त होंगे।

पौधा लगाना को खेत तैयार करना

सर्वप्रथम 30-40 सेंटीमीटर की गहराई तक कुदाली या हल की सहायता से जुताई करें। खेत से पत्थर, झाड़ियों एवं बेकार के खर-पतवार को हटा दें। खेत में अच्छे ढंग से निर्मित 100 किलोग्राम कृमि खाद चारों ओर फैला दें। आवश्यकता के अनुसार 45 सेंटीमीटर या 60 सेंमी की दूरी पर मेड़ या क्यारी बनाएं।

बीज की बुआई, पौध रोपण

सीधे बुआई की जाने वाली सब्जी जैसे ङ्क भिंडी, बीन एवं लोबिया आदि की बुआई मेड़ या क्यारी बनाकर की जा सकती है। दो पौधे 30 सेंटीमी की दूरी पर लगाई जानी चाहिए। प्याज, पुदीना एवं धनिया को खेत के मेड़ पर उगाया जा सकता है। प्रतिरोपित फसल, जैसे ङ्क टमाटर, बैगन और मिर्ची आदि को एक महीना पूर्व में नर्सरी बेड या मटके में उगाया जा सकता है। बुआई के बाद मिट्टी से ढककर उसके ऊपर 250 ग्राम नीम के फली का पाउडर बनाकर छिड़काव किया जाता है ताकि इसे चीटियों से बचाया जा सके। टमाटर के लिए 30 दिनों की बुआई के बाद तथा बैगन, मिर्ची तथा बड़ी प्याज के लिए 40-45 दिनों के बाद पौधे को नर्सरी से निकाल दिया जाता है। टमाटर, बैगन और मिर्ची को 30-45 सेंमी की दूरी पर मेड़ या उससे सटाकर रोपाई की जाती है। बड़ी प्याज के लिए मेड़ के दोनों ओर 10 सेंटीमी की जगह छोड़ी जाती है। रोपण के तीसरे दिन पौधों की सिंचाई की जाती है। प्रारंभिक अवस्था में इस प्रतिरोपण को दो दिनों में एक दिन बाद पानी दिया जाए तथा बाद में चार दिनों के बाद पानी दिया जाए। सब्जी बगीचा का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है तथा वर्षभर घरेलू साग-सब्जी की आवश्यकता की पूर्ति करना है। बगीचा के एक छोर पर बारहमासी पौधों को उगाएं। इससे इनकी छाया अन्य फसलों पर न पड़े तथा अन्य साग-सब्जी फसलों को पोषण दे सकें। बगीचा के चारों ओर तथा आने-जाने के रास्ते का उपयोग विभिन्न अल्पाविध हरी साग-सब्जी जैसे - धनिया, पालक, मेथी, पुदीना आदि उगाने के लिए किया जा सकता है।

महीश तीक्षणा बने वनडे में हैट्रिक लेने वाले श्रीलंका के 7वें गेंदबाज, न्यूजीलैंड ने जीता मैच

हैमिल्टन, एजेंसी। महीश तीक्षणा ने बुधवार को वनडे क्रिकेट में हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। वह श्रीलंका के के सातवें गेंदबाज हैं, जिन्होंने यह कारनामा किया है। तीक्षणा की यह हैट्रिक तीन मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे में सेडन पार्क में हुई। यह सीरीज श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही है। मेहमान टीम की ओर से तीक्षणा ने यह उपलब्धि दो ओवरों में हासिल की। 35वें ओवर में, उन्होंने लगातार दो गेंदों पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर और नाथन स्मिथ को आउट किया। इसके बाद 37वें ओवर की पहली ही गेंद पर मैट हेनरी को पवेलियन भेजकर अपनी हैट्रिक पूरी की।

तीक्षणा ने 8 ओवर में 44 रन देकर 4 विकेट झटके और अपनी स्पिन गेंदबाजी का बेहतरीन प्रदर्शन किया। यह श्रीलंका के किसी गेंदबाज द्वारा छह साल बाद वनडे में हैट्रिक है। इससे पहले 2018 में दुश्मंथा मदुशनका ने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी। महीश तीक्षणा अब श्रीलंका के उन चुनिंदा गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने वनडे में हैट्रिक ली है। इनमें चमिंडा वास, लसिथ मलिंगा, दिलशान मदुशनका, थिसारा परेरा, परवेज महरूफ और वानिंदु हसरंगा जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं।

न्यूजीलैंड की पारी की बात करें तो रचिन रवींद्र ने 79 और मार्क चैपमैन ने 62 रनों की पारी खेली। बारिश के कारण खेल देर से शुरू हुआ और मैच 37 ओवर का कर दिया गया। न्यूजीलैंड ने 255/9 का स्कोर बनाया। इसके बाद श्रीलंका की टीम मात्र 30.2 ओवर में 142 रनों पर आउट हो गई। इस तरह से बारिश से प्रभावित मुकाबले में श्रीलंका को 113 रनों से करारी हार मिली। श्रीलंका की ओर से कामिंदु मेंडिस ने 66 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली। कोई और बल्लेबाज खास योगदान नहीं कर सका। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में मैक हेनरी, नाथन स्मिथ और मिशेल सेंटनर को एक-एक विकेट मिला। विलियम ओरुरके ने सर्वाधिक 3 और जैकब डफी को 2 विकेट मिले। यह तीन मैचों की वनडे सीरीज है जिसमें कीवी टीम ने 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है।

रणतुंगा ने दो स्तरीय टेस्ट क्रिकेट के खिलाफ चेतावनी दी

नई दिल्ली, एजेंसी। श्रीलंका के 1996 विश्व कप विजेता कप्तान और क्रिकेट आइकन अर्जुन रणतुंगा ने क्रिकेट के बिग थ्री - भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया - द्वारा टेस्ट क्रिकेट परिदृश्य को पुनर्गठित करने के प्रस्ताव के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। तीनों शक्तिशाली देश एक दो स्तरीय प्रणाली बनाने की योजना बना रहे हैं जो अपने बीच मैचों को प्राथमिकता देगी, जिससे अन्य क्रिकेट खेलने वाले देशों को द्वितीयक दर्जा मिलेगा। रणतुंगा को डर है कि इस कदम से खेल के विकास को गंभीर नुकसान हो सकता है, खासकर छोटे क्रिकेट खेलने वाले देशों में।

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय, अंग्रेजी और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख इस महीने के अंत में विवादास्पद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए आईसीसी अधिकारियों से मिलने वाले हैं।

एजेंडे में बिग थ्री के बीच टेस्ट मैचों की आवृत्ति बढ़ाने की योजना शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ये टीमें हर चार साल में एक बार के बजाय हर तीन साल में दो बार एक-दूसरे के साथ खेलें। इस व्यवस्था से श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज जैसे अन्य देशों के खिलाफ़ मैचों के लिए कम जगह बचेगी, जिससे बिग थ्री के बाहर की टीमें प्रभावी रूप से हाशिए पर चली जाएंगी।

क्या गुरु गंभीर के दबाव में रोहित और विराट खेलेंगे रणजी ट्रॉफी?

नईदिल्ली, एजेंसी। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट में फ्यूचर बचा हुआ है? यह सवाल हेड कोच गौतम गंभीर से पूछा गया था. इस इस पर गंभीर ने कहा, यह उन पर निर्भर करता है. वहीं गंभीर ने यह भी स्पष्ट किया कि वह चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में खेलने वाले खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट को गंभीरता से लें और अगर वे कहीं और खेलने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं तो रणजी ट्रॉफी खेलें.

यानी एक बात तो साफ है कि इशारों- इशारों में हेड कोच गौतम गंभीर ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि कोहली और रोहित को घरेलू क्रिकेट में, खास तौर पर रेडबॉल क्रिकेट खेखेलने के लिए उतरना होगा. भारत के कई सुपर स्टार क्रिकेटर घरेलू क्रिकेट के रेड बॉल फॉर्मेट (फर्स्ट क्लास क्रिकेट) से लंबे समय से दूर हैं. विराट कोहली (2 से 5 नवंबर) ने आखिरी बार 2012 में घरेलू लाल गेंद क्रिकेट खेला था, रोहित शर्मा ने 2015 (7 से 10 नवंबर) में खेलते हुए दिखे थे. कोहली ने यह मुकाबला गाजियाबाद में यूपी के खिलाफ खेला, जहां उन्होंने दोनों पारियों में 14 और 43 रन बनाए. वहीं रोहित आखिरी बार फर्स्ट क्लास मैच यूपी के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेलते दिखे थे, जहां उन्होंने 113 रनों की शानदार पारी खेली. पिछले चार वर्षों में शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा , मोहम्मद सिराज और केएल राहुल ने कुल मिलाकर सिर्फ चार लंबे फॉर्मेट वाले घरेलू मैच खेले हैं.

आंकड़े खुद ही सब कुछ बयां कर रहे हैं. भारत की टेस्ट टीम के मुख्य खिलाड़ी बमुश्किल ही घरेलू मैदानों पर खेलते हैं, और लाल गेंद से मैच खेलने का अभ्यास न होने का असर इंटरनेशनल नतीजों पर पड़ रहा है.

रोहित शर्मा की अगुआई वाली भारतीय टीम ने एक दशक बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गत रविवार को ऑस्ट्रेलिया के सामने सरेंडर कर दी. इससे पहले टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था. इन दो झटकों के कारण ही भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने से चूक गया.

कोहली ने BGT के 5 टेस्ट मैचों में 190 रन 23.75 के एवरेज से बनाए. वहीं रोहित शर्मा का तो बल्ले से बहुत ही बुरा हाल रहा. रोहित शर्मा ने 3 मैचों में महज 31 रन 6.20 के एवरेज साथ बना पाए. वहीं कई दिग्गज क्रिकेटर भी रोहित शर्मा और कोहली को घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह दे चुके हैं.

इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 14 जनवरी से

- 20 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, सिंधु शादी के बाद पहली बार खेलेंगी, लक्ष्य के साथ दल की अगुआई करेंगी

नईदिल्ली, एजेंसी। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत इस बार 20 खिलाड़ियों का दल उतारेगा। पिछले सीजन में 14 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए थे। लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय दल की अगुआई करेंगे।

यह टूर्नामेंट 14 जनवरी से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जाधव इंडोर हॉल में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में ओलिंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन, एन से यंग और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी शि यूकी जैसे सुपरस्टार भी खेलते नजर आएंगे।

भारतीय बैडमिंटन संघ के महासचिव संजय मिश्रा ने बयान जारी कर कहा कि सुपर 750 प्रतियोगिता में इतने सारे भारतीय खिलाड़ियों का भाग लेना बताता है कि वर्ल्ड लेवल पर भारत के बैडमिंटन ने कितना विकास किया है। यह विश्व मंच पर भारतीय बैडमिंटन के विकास और उत्थान का एक संकेत है। उन्होंने आगे कहा कि यह तो बस शुरुआत है। 2025 एक ऐसा साल होगा, जिसमें बड़े नामों के साथ-साथ और भी नाम शामिल होंगे।

सात्विक साई राज पिछले साल सेमीफाइनल में पहुंचे थे। मेंस डबल्स में चिराग-सात्विक साईराज करेंगे अगुआई चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी मेंस डबल्स में भारतीय टीम की अगुआई करेंगे। दोनों की जोडी पिछले साल फाइनल में पहुंची थी, हालांकि टाइट जीतने में सफल नहीं हो सके थे। पेरिस ओलिंपिक के बाद चोट के कारण सात्विक बहुत ज्यादा मैदान पर नहीं दिखे हैं।

ऐसे में इस टूर्नामेंट से उनके पास फॉर्म हासिल करना बड़ी चुनौती होगी। सिंधु का शादी का पहला इवेंट दो ओलिंपिक मेडल जीत चुकी पीवी सिंधु का शादी के बाद यह पहला इवेंट है। उन्होंने 22 दिसंबर, 2024 को हैदराबाद के वेंकट दत्ता साई से शादी की।

22 दिसंबर, 2024 को जयपुर में हैदराबाद के बिजनेस मैन से शादी की।

विमेंस प्रीमियर लीग लखनऊ और बड़ौदा में होगी

नईदिल्ली, एजेंसी। विमेंस प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन के लिए बीसीसीआई ने 2 वेन्यू फाइनल कर लिए हैं। बड़ौदा और लखनऊ में 5 टीमों के बीच सभी मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट 6 या 7 फरवरी से शुरू हो सकता है।

बड़ौदा में सेकेंड फेज के मैच होंगे, जिनमें क्वालिफायर और फाइनल भी शामिल हैं। टूर्नामेंट का ऑफशियल शेड्यूल रिलीज होना बाकी है। हालांकि, बोर्ड ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को उनके ग्राउंड पर मैच कराने की जानकारी दे दी है। शेड्यूल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों में हो जाएगा है।

बड़ौदा के कोटाम्बी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिसंबर 2024 में विमेंस वनडे के 3 मैच खेले गए थे। बड़ौदा में विमेंस इंटरनेशनल मैच हुआ था बड़ौदा में कोटाम्बी स्टेडियम है, जिसका उद्घाटन पिछले महीने ही हुआ था। यहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच खेला गया था। यहां 3 वनडे हुए थे। इस स्टेडियम में सीनियर विमेंस टी-20 टूर्नामेंट और रणजी ट्रॉफी के मैच भी हो चुके हैं। स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लग चुके हैं। 9 जनवरी से शुरू होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट मैच यहां होंगे, इसमें इन लाइट्स की टेस्टिंग भी हो जाएगी। टूर्नामेंट का फाइनल 8 या 9 मार्च को हो सकता है।

बेन स्टोक्स को हॉस्पिटल में कराना पड़ा एडमिट, हुआ बड़ा ऑपरेशन

लंदन, एजेंसी। इंग्लैंड की टीम पिछले साल दिसंबर के महीने में न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी. इस टेस्ट सीरीज के अंतिम मुकाबले में उन्हें हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो गई थी. अब इस इंजरी की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में जाकर एक बड़ी सर्जरी करानी पड़ी है. उन्होंने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया पर ताजा अपडेट दिया है. स्टोक्स ने सर्जरी के बाद अपने पांव की तस्वीर शेयर की, जिसमें वह पैर में ब्रेस लगाए हुए नजर आ रहे हैं. वो कार में हैं और अपने पांव के नीच तकिया भी रखा हुआ है. तस्वीर को देखकर कहा जा सकता है कि इंजरी गंभीर थी, जिसके लिए बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा. अब सवाल है कि आखिर अब वो मैदान पर कब तक वापसी करेंगे?

सर्जरी के बाद बेन स्टोक्स के पांव में लगे मशीन को देखने के बाद सवाल गहरा गया कि आखिर वो कब तक मैदान से बाहर रहेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें पूरी तरह से रिकवरी करने में 3 महीने का समय लगेगा. हालांकि, उन्होंने अपनी पोस्ट में हिंट देते हुए बताया है कि वो जल्दी ही एक्शन में देखेंगे. इंग्लैंड के कप्तान ने लिखा 'सर्जरी हुई है. इसलिए कुछ दिनों के लिए बायोनिक मैन बना हुआ हूं. जल्दी ही वापसी करुंगा.' उनकी पोस्ट पर कई फैंस ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की है.

चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर स्टोक्स

बेन स्टोक्स इंग्लैंड की टीम का अहम हिस्सा हैं. श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी वो इंजरी का शिकार थे. इसके बाद वो न्यूजीलैंड दौरे पर पूरी तरह फिट होकर कप्तान और ऑलराउंडर की भूमिका में लौटे. लेकिन हेमिल्टन में मैच के दौरान उन्होंने अचानक हैमस्ट्रिंग की समस्या हुई बीच में ही मैच छोड़कर जाना पड़ा.

वो 2023 वनडे वर्ल्ड कप हिस्सा था और पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाले थे. लेकिन इंजरी के कारण हुई सर्जरी के बाद उन्हें रिकवरी में थोड़ा समय लग सकता है. इसलिए फरवरी में शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट से उन्हें पहले ही बाहर कर दिया गया है. इंग्लैंड ने अपने स्क्वॉड में उन्हें जगह नहीं दी है. वहीं मई तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं होने के कारण वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर ही रहेंगे और अपनी रिकवरी पर फोकस करेंगे.

ऑस्कर 2025 के दावेदारों में कंगुवा ने बनाई जगह, 323 फिल्मों को दिया टकराव

दक्षिण भारतीय स्टार सूर्या और 'एनिमल' फेम बॉबी देओल स्टारर 'कंगुवा' पिछले साल रिलीज हुई थी। इस फिल्म के सिनेमाघरों में पहुंचने से पहले दर्शकों में जबरदस्त क्रेज था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। फिल्म को लाउड साउंड स्कोर और दूसरे एक्टर्स के कम स्क्रीन टाइम के चलते यूजर्स ने सोशल मीडिया पर काफी ट्रॉल किया। हालांकि अब 'कंगुवा' को लेकर एक बहुत अच्छी खबर आ रही है।

सिरुथाई शिवा के डायरेक्शन में बनी

फिल्म ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 'कंगुवा' ने लगभग 323 ग्लोबल फिल्मों को टक्कर देते हुए ऑस्कर 2025 के दावेदारों की लिस्ट में जगह बना ली है। फिल्म इंडस्ट्री ट्रैकर मनोबाला विजयबालन ने एक्स (ट्विटर) पर यह खबर शेयर की है। उनके ट्वीट में दावेदारों की सूची और सूर्या के पोस्टर के साथ लिखा गया है, ब्रेकिंग कंगुवा ने ऑस्कर 2025 में एंट्री की। जैसे ही यह खबर सामने आई इंटरनेट पर वायरल हो गई। फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

कंगना ने अपनी फिल्म इमरजेंसी में कुछ सीन काटे जाने पर की बात

आगामी फिल्म इमरजेंसी में नजर आने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म से कुछ अंश हटाने के आदेश पर प्रतिक्रिया दी।

अभिनेत्री ने बात करते हुए बताया कि एक निर्देशक के तौर पर वह मूल कथानक वाली फिल्म ही चाहती थीं। हालांकि, वह सीबीएफसी के फैसले को स्वीकार करती हैं। कंगना ने कहा कि मैं चाहती थी कि इसका पूरा संस्करण आए। लेकिन कट के साथ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिल्म किसी का मजाक उड़ाने के लिए बनाई गई है।

राम चरण ने दुर्घटना में मारे गए फैंस के परिवारों को 10 लाख रुपये की मदद दी

गेम चेंजर के प्री-रिलीज़ इवेंट का आयोजन 4 जनवरी को राजमहेंद्रवरम में हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यहां दुख की बात यह है कि दो फैंस–जो काकीनाडा जिले के गैगोलुपाडू के निवासी थे, इवेंट से घर लौटते वक्त एक दुर्घटना का शिकार हो गए। उनकी बाइक को एक वैन ने वाडीसलेरू के पास टक्कर मारी, जिससे दोनों की असमय मौत हो गई।

इस घटना से गहरे दुखी राम चरण ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। घटना की जानकारी मिलते ही, उन्होंने तुरंत अपनी टीम को परिवारों को सांत्वना देने के लिए भेजा। इसके साथ ही, उन्होंने दोनों परिवारों को प्रत्येक को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की, ताकि इस कठिन समय में उनकी मदद हो सके। राम चरण की यह दयालु भावना उनके प्रशंसकों द्वारा सराही गई है, जो उनकी अपने समर्थकों के प्रति चिंता और प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

संक्षिप्त समाचार

अब इंदिरा भवन होगा कांग्रेस का नया मुख्यालय

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी आगामी 15 जनवरी को पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन करेंगी। पिछले करीब पांच दशक से पार्टी का मुख्यालय 24अकबर रोड था। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया, 15 जनवरी, 2025 को सुबह 10 बजे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी जी नए एआईसीसी मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन का उद्घाटन करेंगी। इसका निर्माण कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य, स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्य, कांग्रेस संसदीय दल के पदाधिकारी, एआईसीसी पदाधिकारी, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख, सीएलपी नेता, सांसद, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित वरिष्ठ नेता इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। वेणुगोपाल के अनुसार, 9ए, कोटला मार्ग पर स्थित इंदिरा गांधी भवन को पार्टी और उसके नेताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रशासनिक, संगठनात्मक और रणनीतिक कार्यों में सहयोग करने के लिए आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा, यह प्रतिष्ठित इमारत कांग्रेस पार्टी के असाधारण अतीत को श्रद्धांजलि देते हुए उसकी दूरदर्शी दृष्टि को दर्शाती है, जिसने भारत के राजनीतिक और सामाजिक ताने-बाने को आकार दिया है। कांग्रेस के नए मुख्यालय का काम पिछले कई वर्षों से जारी था। सूत्रों ने कहा कि पार्टी अपने वर्तमान मुख्यालय 24, अकबर रोड को फिलहाल खाली नहीं करेगी, जो 1978 में कांग्रेस (आई) के गठन के बाद से इसका मुख्यालय रहा है। सूत्रों ने कहा कि शुरुआत में प्रशासन, लेखा और कुछ अन्य कार्यालय नए भवन में स्थानांतरित होंगे। कांग्रेस के विभिन्न अग्रिम संगठन - महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई और पार्टी के विभाग और प्रकोष्ठ के कार्यालय भी नए परिसर में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि 1977 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद लुटियंस दिल्ली में 24, अकबर रोड बंगले को एआईसीसी मुख्यालय में बदल दिया गया था।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2025 के लिए सरकारी कैलेंडर का अनावरण किया

नईदिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को 2025 के लिए सरकारी कैलेंडर का अनावरण किया, जिसमें जनभागीदारी से जनकल्याण की विषयवस्तु पर प्रकाश डाला गया। वैष्णव ने कहा कि कैलेंडर में पिछले दशक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में शासन के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाया गया है। कैलेंडर के अनावरण के अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू, पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के प्रधान महानिदेशक धीरेंद्र ओझा और केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक योगेश बावेजा मौजूद थे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार के कैलेंडर में पिछले कई वर्षों से प्रमुख कार्यक्रमों, पहल और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। कैलेंडर 13 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हुआ है।

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राजघाट परिसर में बनेगी प्रणब मुखर्जी की समाधि

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्मृति परिसर यानी राजघाट परिसर के अंदर एक विशेष स्थल को चिन्हित करने को मंजूरी दी है। लेखिका और प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और बाबा के लिए एक स्मारक बनाने के उनके सरकार के फैसले के लिए दिल से आभार और कृतज्ञता व्यक्त की। यह और भी अधिक सराहनीय है, क्योंकि हमने इसके लिए नहीं कहा था।

दिल्ली में कांग्रेस की राह नहीं आसान, जनाधार वापस पाना चुनौती

नईदिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली की सत्ता में लगातार तीन बार काबिज रही कांग्रेस के लिए इस विधानसभा चुनाव में अपने जनाधार को वापस पाना बड़ी चुनौती है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति पिछले एक दशक में लगातार कमजोर होती दिखाई दी है। जहां 2013 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, वहीं 2015 और 2020 के चुनाव में पार्टी ने अपनी जमीन लगभग खो दी।

2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज आठ सीट पर जीत मिली, जबकि इससे पहले शीला दीक्षित के नेतृत्व में पार्टी ने लगातार 15 वर्ष तक राजधानी में शासन किया था। 2015 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन और भी खराब रहा, जब उसे एक भी सीट नहीं मिली। वोट शेयर घटकर 9.7 फीसदी रह गया। 2020 के चुनाव में भी पार्टी कोई सुधार नहीं कर सकी और उसका मत प्रतिशत गिरकर 4.26 फीसदी हो गया।

2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस का मत प्रतिशत लगभग 18.91 फीसदी रहा, जो पार्टी के लिए थोड़ा राहतभरा संकेत हो सकता है। हालांकि, यह सुधार विधानसभा चुनाव में कितनी प्रासंगिकता रखेगा, यह कहना मुश्किल

है। एक दशक से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में मजबूत और प्रभावी नेतृत्व का अभाव एक बड़ी समस्या है। शीला दीक्षित के निधन के बाद पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है, जो जनता के बीच उनकी छवि को दोहरा सके।

दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल पर निजी हमलों में नरम दिखेगी कांग्रेस: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। प्रदेश कांग्रेस एक के बाद एक चुनावी गारंटियों का ऐलान कर रही है। सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने से जहां कार्यकर्ता उत्साहित हैं, वहीं पार्टी को अपना 11 वर्ष पुराना प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद है। इस सबके बावजूद पार्टी विपक्षी एकता को दांव पर नहीं लगाना चाहती है। इस कारण माना जा रहा है कि केजरीवाल पर चुनावी हमले में कांग्रेस नरम रुख अपना सकती है। कांग्रेस राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ केरल और पंजाब जैसा रिश्ता रखना चाहती है। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ और लेफ्ट के नेतृत्व में बना एलडीएफ आमने-सामने हैं। स्थानीय स्तर पर दोनों पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ हैं पर राष्ट्रीय स्तर पर लेफ्ट पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग-अलग चुनाव लड़ती हैं, पर दिल्ली में दोनों पार्टियों ने गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा था।

11 किमी में बनेंगे 8 इंटरचेंज लूप, एनसीआर से आगरा तक फायदा

यमुना एक्सप्रेसवे को केजीपी से जोड़ने का काम शुरू

नईदिल्ली, एजेंसी।
यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (केजीपी) से जोड़ने के लिए बनने वाले इंटरचेंज का काम शुरू हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की टीम ने मंगलवार को दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बनने वाले इंटरचेंज की जमीन का मौके पर जाकर सर्वेक्षण किया। इंटरचेंज का निर्माण एक वर्ष में पूरा होगा।

अधिकारी ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट से 10 किलोमीटर पर जगनपुर-अफजलपुर में केजीपी को जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। ग्रेटर नोएडा से होकर गुजर रहे केजीपी का यमुना एक्सप्रेसवे से अभी तक कोई लिंक नहीं है। इस वजह से केजीपी पर आगरा जाने वाले वाहन चालकों को 15 से 20 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। वहीं, परी चौक और कासना के जाम से जूझना पड़ता है। फिलहाल सिरसा के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है। दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके निर्माण में करीब 270 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इंटरचेंज को बनाने का काम वर्ष 2023 में शुरू हुआ था। इसके निर्माण में 122 करोड़ रुपये खर्च होने थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही विकासकर्ता कंपनी ने इसके निर्माण में लगने वाली मिट्टी पर खर्च होने वाले 22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त एस्टीमेट

डाल दिया और काम रुक गया। 22 करोड़ का पेच फंसने के चलते कई महीने तक निर्माण नहीं हो सका। इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारियों ने बैठक कर इसके निर्माण की जिम्मेदारी एनएचएआई को सौंपी थी। दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेज पर आठ लूप बनाए जाने हैं, जो कुल 11 किलोमीटर के होंगे। इनमें चार लूप उतरने और चार लूप चढ़ने के लिए बनाए जाएंगे। इससे एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों को इंटरचेंज से उतरने और चढ़ने के लिए जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोनों एक्सप्रेसवे जुड़ने से गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ के लोगों को आगरा की ओर जाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए ग्रेटर नोएडा परी चौक नहीं जाना पड़ेगा।

यह कनेक्टिविटी होने से इन जिलों के वाहन दुहाई और डासना से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पहुंच सकेंगे। वहीं मथुरा, आगरा से आने वाले यात्रियों को पेरिफेरल पर चढ़ने के लिए 20 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना होगा।

दिल्ली चुनाव में काले धन पर लगेगी लगाम, इनकम टैक्स रखेगी नजर; टोल फ्री नंबर जारी, जनता भी कर सकती है मदद

नईदिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सियासी पिच पर राजनीतिक दल खूब वार-पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच आयकर विभाग ने बुधवार को एक 24×7 नियंत्रण कक्ष और शिकायत निगरानी सेल को नोटिफाई (अधिसूचित) किया। आम जनता दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कैश वितरित करने जैसे अवैध प्रलोभनों को लेकर सूचना दे सकते हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को 70 सदस्यीय सदन के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होगी। एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि उसने मध्य दिल्ली के सिविक सेंटर में 24×7 नियंत्रण कक्ष खोला है और एक टोल-फ्री नंबर- 1800111309 भी जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली विधानसभा चुनाव के सिलसिले में दिल्ली के एनसीटी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के अंदर कैश, सर्राफा और कीमती मेटल आदि की संदिग्ध मूवमेंट या वितरण के बारे में विभाग को सूचना दे सकता है। विभाग ने कहा कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। नोटिस में विभिन्न लैंडलाइन और मोबाइल नंबरों के साथ-साथ कंट्रोल रूम का पता भी दिया गया है। विभाग की इन्वेस्टिगेशन शाखा चुनाव आयोग द्वारा अनिवार्य उपायों के तहत प्रत्येक चुनाव वाले राज्य में ऐसे कंट्रोल रूम नोटिफाई करती है, जिसका मकसद मतदाताओं को प्रभावित करने और रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले काले धन के इस्तेमाल को रोकना है, जिससे चुनावी मैदान में संतुलन बिगड़ता है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही, दिल्ली सरकार ने मंगलवार को विभिन्न दिशा-निर्देश जारी कर सरकारी वेबसाइटों पर निर्वाचित सरकार या किसी अन्य पार्टी के राजनेताओं की तस्वीरें और संदर्भ प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी। एक अन्य आदेश में, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के मद्देनजर सरकारी खजाने की कीमत पर सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाले कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट को मिले दो नए जज

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट के बुधवार को दो नए जज मिले हैं। वकील अजय दिगपॉल और हरीश वैद्यनाथन शंकर ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जिसके बाद अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 के मुकाबले 39 हो गई। केंद्र सरकार ने सोमवार को अधिसूचित किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनकी सिफारिश किए जाने के लगभग चार महीने बाद की गई।

अगस्त 2024 में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वकील अजय दिगपॉल और हरीश वैद्यनाथन शंकर को दिल्ली हाईकोर्ट के जज के तौर पर पदोन्नत करने की सिफारिश की थी, जिसमें उनकी पेशेवर क्षमता, ईमानदारी और विशेष विशेषज्ञता को अंडरस्कोर किया गया था। कंपनी, सेवा और वाणिज्यिक कानून सहित कानून के विभिन्न क्षेत्रों में उनके 31 साल के अनुभव और 42 रिपोर्ट किए गए निर्णयों में उनकी उपस्थिति को ध्यान में रखा था।

दिल्ली में छोटे दल बिगाड़ेंगे बड़ों-बड़ों का खेल? ओवैसी से एनसीपी-बीएसपी तक सब मैदान में कूदे

नईदिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली में इस बार छोटे दल बड़ों-बड़ों का खेल बिगाड़ने की तैयारी में हैं। बसपा, सपा और जदयू पहले भी यहां चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार ओवैसी की एआईएमआईएम, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और अजित पवार की एनसीपी ने ताल ठोककर प्रमुख दलों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने दिल्ली के सियासी दंगल में ताल ठोक दी है। ओवैसी सभी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। अब तक वह मुस्तफाबाद से दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन और ओखला से शफाउर रहमान खान को टिकट दे चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एआईएमआईएम अगर चुनाव में उतरती है तो मुस्लिम समाज का एक बड़ा धड़ा उनके साथ जा सकता है। मुस्लिम बाहुल्य सीट मुस्तफाबाद, ओखला, सीलमपुर,

बल्लीमरान, मटियामहल और बाबरपुर में नतीजे बदल सकते हैं।

दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का वैसे तो बीते चुनाव में कोई जनाधार नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बसपा ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 'एक्स' पर लिखा कि, दिल्ली का चुनाव उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। बसपा का यह कदम उसके लिए कितना फायदेमंद और दूसरों के लिए कितना नुकसानदायक होगा, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान भतीजे व राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर आकाश आनंद को सौंपी है। यूपी में पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोलने वाले चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने दिल्ली चुनाव में उतरने का फैसला किया है। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। बसपा के साथ-साथ चंद्रशेखर अपनी सक्रियता बढ़ाते हैं तो दिल्ली की सियासत की तस्वीर बदल सकती है।

सिंध प्रांत में हिंसक हुआ अतिक्रमण हटाने का अभियान, अधिकारियों-भीड़ के बीच झड़प

हैदराबाद शहर के कासिमाबाद इलाके में हुई झड़प

इस अभियान का नेतृत्व सिंचाई विभाग कर रहा है

कराची , एजेंसी।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अतिक्रमण हटाने का अभियान हिंसक हो गया है, जिससे अधिकारियों और भीड़ के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में कम से कम 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये झड़पें मंगलवार को

हैदराबाद शहर के कासिमाबाद इलाके में हुईं।

अधिकारियों को स्थानीय लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जब वे एक सिंचाई चैनल को बहाल करने और जमीन पर 24 फुट चौड़ी सड़क बनाने के लिए अतिक्रमण और संरचनाओं को हटाने के लिए एक मजबूत पुलिस बैकअप के साथ पहुंचे। अतिक्रमित संरचनाओं के निवासियों ने अधिकारियों पर पथराव किया, जिससे कुछ सरकारी गाड़ियों के शीशे टूट गए। जब कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की और भारी आंसू गैस के गोले छोड़े तो प्रदर्शनकारी भीड़ के लगभग 12 नागरिक भी घायल हो गए।

हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) जैनुल आबिदीन मेमन ने हिंसा की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, भीड़ के साथ-साथ कुछ नागरिकों की तरफ से की गई हिंसा में लगभग 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्होंने कहा कि पिछले दिन की झड़प के बाद आज बुधवार को भी अभियान जारी था।

ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, पैसे देकर चुप कराने के मामले में नहीं मिली राहत

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में सजा पर सुनवाई पर रोक को लेकर उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. न्यूयॉर्क अपील कोर्ट के जज ने ट्रंप के अनुरोध को खारिज कर दिया. मामले में शुक्रवार सजा पर फैसला सुनाया जाना है. ट्रंप अब अपीलीय अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और सजा पर स्टे लगाने का अनुरोध कर सकते हैं. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार एसोसिएट जस्टिस एलेन गेस्मर ने मंगलवार दोपहर मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद ट्रंप के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया. ट्रंप ने मंगलवार को चुप रहने के लिए धन देने के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. ट्रंप के वकील टॉड ब्लैंच ने मंगलवार को अदालत से कहा कि उन्हें ट्रंप की सजा पर रोक लगा देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि स्थिति अभूतपूर्व थी. ट्रंप ने टॉड ब्लैंच को नई सरकार के लिए प्रशासन में डिप्टी अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना है. सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले गेस्मर ने ट्रम्प के वकील से पूछा कि क्या उनके अनुरोध के लिए कोई मिसाल है कि राष्ट्रपति पद की छूट को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति तक बढ़ाया जा सकता है. जवाब में उन्होंने कहा, इस तरह का मामला पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए नहीं. मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय के अपील प्रमुख स्टीवन वू ने कहा कि ट्रम्प के वकीलों ने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है कि सजा पर सुनवाई से ट्रंप की अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारियों में बाधा उत्पन्न होगी. वू ने कहा, अब ऐसा करने का सबसे अच्छा समय है. वू ने कहा, किसी न किसी समय तो सजा सुनाई ही जानी चाहिए।

युगांडा में एमपॉक्स से मरने वालों की संख्या हुई 10 : स्वास्थ्य मंत्रालय

कंपाला, एजेंसी।
पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा में पिछले पांच दिनों में चार लोगों की मौत रिपोर्ट हुई। इसके बाद एमपॉक्स से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। एक रिपोर्ट में युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले पांच दिनों में कम से कम 156 नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। जिससे देश में संक्रमण से जूझ रहे लोगों की कुल संख्या 1,571 हो गई। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने मंत्रालय के हवाले से कहा कि पिछले 24 घंटों में 19 नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 17 मामले वाकिसो के केंद्रीय जिले में, एक युगांडा की राजधानी कंपाला में और एक लीरा में दर्ज किए गए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और साझेदारों के सहयोग से मंत्रालय ने रोग के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम उपायों को तेज कर दिया है, जिसमें निगरानी, मामला प्रबंधन, स्वास्थ्य बैठकें आयोजित करना, जोखिम संचार और सामुदायिक सहभागिता तथा जन जागरूकता अभियान शामिल हैं।

एमपॉक्स एक बीमारी है जो मंकीपॉक्स वायरस के कारण होती है। यह एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से निकट संपर्क के माध्यम से लोगों के बीच फैल सकता है। एमपॉक्स के सामान्य लक्षणों में दाने, बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा और ग्रंथियों में सूजन शामिल हैं।

पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि अफ्रीका में एमपॉक्स की महामारी संबंधी स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बनी हुई है, तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी), बुरुंडी और युगांडा में इसके मामले अधिक संख्या में देखे गए हैं। डब्ल्यूएचओ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 15 दिसंबर तक अफ्रीका में 20 देशों में 13,769 पुष्ट मामले सामने आए हैं, जिनमें 60 मौतें शामिल हैं। सबसे अधिक प्रभावित देश डीआरसी है, जहां 9,513 पुष्ट मामले पाए गए हैं।

हालांकि डीआरसी में हाल के सप्ताहों में अपेक्षाकृत स्थिर महामारी की प्रवृत्ति देखी गई है, फिर भी डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि संभावित रिपोर्टिंग देरी को देखते हुए स्थिरता और गिरावट की प्रवृत्ति की सावधानीपूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि डीआरसी के बाहर क्लेड 1बी एमपॉक्स वायरस (एमपीएक्सवी) के भौगोलिक विस्तार की रिपोर्ट जारी है, साथ ही कहा कि अफ्रीका के बाहर आठ देशों में इस वायरस का पता चला है।

लॉस एंजिल्स के जंगलों में लगी भीषण आग ने मचाई तबाही, 30 हजार लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी

न्यूयॉर्क, एजेंसी। दक्षिणी कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में लगी भयंकर आग विकराल रूप ले चुकी है। हजारों लोगों को रिहायशी इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा गया है। लॉस एंजिल्स के पहाड़ी इलाकों में लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन दल ने कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आग की लपटें मीलों तक फैली हुई हैं। लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट की फायर चीफ क्रिस्टिन क्राउली ने बताया कि 10,000 से अधिक घरों और 13,000 से अधिक इमारतों में रहने वाले करीब 26,000 लोग आग से प्रभावित हुए हैं। बड़ी तादात में लोग अपनी कारों को छोड़कर पैदल ही सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि सड़कें भीषण आग के चलते अवरुद्ध हैं। आग को तेज हवाओं ने और बढ़ा दिया है। कैलिफोर्निया के लाखों लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही लोगों को आग के और फैलने का खतरे से आगाह किया गया है। इसके साथ ही बड़े इलाके की बिजली सप्लाई को बंद कर दिया गया है। जिसके चलते करीब पांच लाख लोग प्रभावित हुए हैं। पश्चिमी लॉस एंजिल्स के पैसिफिक पैलिसेड्स में आग ने लगभग 2 वर्ग मील से अधिक जंगल को जला दिया है। जिससे पूरे शहर में धुएं गुबार देखा जा सकता है। खराब मौसम के कारण राष्ट्रपति जो बाइडन ने कैलिफोर्निया के रिवरसाइड काउंटी की यात्रा रद्द कर दी हैं।

स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रकः- देवेन्द्र मालवीय द्वारा श्री सिंध्दी विनायक प्रिंटर्स 26 बी देशबंधु परिसर प्रेस काम्प्लेक्स झोन 1 एम पी नगर भोपाल म.प्र. से मुद्रित एवं 773 / 19 मेघदूत नगर इंदौर म.प्र. से प्रकाशित सम्पादक डॉ. देवेन्द्र मालवीय
कार्यालय पताः-एच. 21 अंकित अपार्टमेंट ब्रजेश्वरी एनएक्स, इंदौर मध्यप्रदेश मोः- 98276-22204 सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इंदौर रहेगा। डाक पंजीकरण संख्या-MP/IDC/1619/2024-2026

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त सूचनाए, विचार,आलेख विभिन्न समाचार के स्त्रोत एवं संकलन लेखकों के व संकलनकर्ता के स्वंय जिनका संकलन विभिन्न एजेंसियों, के माध्यम से किया गया है, अतः समस्त प्रकार के प्रकाशन हेतु संपादक, प्रकाशक, मुद्रक का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहमत होना अनिवार्य नही है।